भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

जनसंग्राम

चुनाव बहिष्कार विशेषांक

अंक 3 - मार्च 2014 - सहयोग राशि 15रु.

लोकसभा व ओड़िशा विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

चुनावों से जनता की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता.

सच्चे जनवाद के लिए माओवादी जनयुध्द की राह चुनो!

प्यारी जनता

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में चुनावी नाटक शुरु हो गया है. चुनाव आयोग ने 9 चरणों में लोकसभा व ओड़िशा सहित तीन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है. रंग-बिरंगी टोपियों वाली पार्टियां, जो पांच साल तक लूट करने में मस्त रही अब फिर आपके सामने हाथ जोड़ कर आना शुरु कर दी हैं. पिछली बार प्रति उम्मीद्वार 40 लाख खर्च करने की अनुमति थी अब कि बार 70 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दे दी है. पिछले चुनावों के नाटक पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे. इस बार भी जनता के खून पसीने की गाढी कमाई पानी की तरह बहायी जायेगी.

हमारी पार्टी नक्सलबाड़ी के समय से ही कहती आई है कि संसद केवल और केवल गुंडों का अखाड़ा है, और यह सच समय-समय पर सबित होता आया है. सच्चाई यही है कि भारत में बुर्जुआ जनवादी क्रांति सफल नहीं हुई और भारत की 'संसदीय व्यवस्था' ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा थोपी गयी संसदीय व्यवस्था है न कि जनवादी क्रांति का फल ! 1947 के बाद से भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद सहित अन्यन्य साम्राज्यवादियों के लिए नव उपनिवेशिक व्यवस्था के तहत लूट का स्रोत बन गया है.

भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला 1 लाख 76 हजार, कोयला खदान घोटाला 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये, और कॉमन वेल्थ खेल घोटाला 60 हजार करोड़ रुपये, कुल मिलाकर देखा जाये तो आए दिन एक नया घोटाला सामने आता रहा है. वहीं कांग्रेस राग अलाप रही है 'हो रहा भारत निर्माण'! दरअसल कांग्रेस ने भारत का निर्माण नहीं बल्कि पूंजीपतियों का निर्माण किया है. विकास के नाम पर 400 से ज्यादा विशेष आर्थिक जोनों को मंजूरी दी गयी, जिससे लाखों एकड़ भूमि किसानों की छीन ली, खदानों व बड़े बांधों के निर्माण के लिए हजारों आदिवासियों की जमीनों, जंगलों को बर्बाद किया जा चुका है. जब किसान, आदिवासी अपने जल-जंगल-जमीन के लिए जीवन मरण के संघर्ष पर उतारु हो गए तो उसको भटकाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून आदि लेकर आए. जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया, सरकार से जवाब मांगे जाने लगे तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए सूचना का अधिकार लाए. मनरेगा नाम से रोजगार गारंटी स्कीम चला रहे हैं और किसानों को उजाड़ कर, उन्हें मजदूर बना रहे हैं दस साल में ये कानून, वो कानून जो कांग्रेस बता रही है, सबके सब इस शोषक व्यवस्था को बचाने के लिए ही लाए गए कानून हैं. देश का विकास नहीं विनाश किया गया है. विकास दर 4.8 पर आकर गिर गयी है. मजदूरों, कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया गया है. छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं. बड़े कारखानों में लगातार छंटनी जारी हैं. जिससे लाखों मजदूरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है. खुदरा व्यापारियों के पेट पर ठोकर मारते हुए खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश को लागू कर दिया है. महिलाओं से सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, देश की राजधानी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित

संसद सुअर बाड़ा है - गुंडो का अखाड़ा है!

नोट से ना वोट से - हक मिलेंगे चोट से!!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

जनसंग्राम

इस अंक में

संपादकीय
चुनावों के बहिष्कार पर ....
पहले कवर पेज से
हम चुनावों का बहिष्कार क्यों करते हैं?
पेज 04
भारत में नवजनवादी क्रांति के बाद का कार्यक्रम
पेज 05
ओड़िशा को बेच खाया नवीन पटनायक ने
पेज 09
'आप' के मुखिया से दस सवाल
पेज 11
ओड़िशा की जनता के लिए बॉक्साईट खनिज बना अभिशाप
पेज 14
कंपनियों को खजाना और जनता को मौत बांटती सरकार
पेज 17
सैध्दांतिक लेख - कार्यशैली स्तालिन
पेज 18
श्रृंखला - भगतसिंग की बात सुनो माओवाद की राह चुनो
लेख - विद्यार्थी और राजनीति
पेज 20
रिपोर्ट
भारतीय जेलों में गुंजे नारे 22
जनता पर युध्द 'ओजीएच' का तीसरा चरण शुरु
पेज 23
ओएससी स्टेटमेंट्स
गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रुप में मनाओ 26
श्रधांजली
आकुला भूमिया और गंटी प्रसाद को
पेज 28
पर्चा तेंदुपत्ता पर 20
गरियाबंद पुलिस के दुश्प्रचार का जवाब 31
25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की रिपोर्ट 33

पत्रिका एक संगठनकर्ता भी होती है!

- कामरेड लेनिन

स्थान है. इसका कारण है साम्राज्यवादियों की नई आर्थिक नीतियों के तहत पश्चिम संस्कृति को भी शासक वर्गों ने आयात किया है. कृषि लगातर घाटे का सौदा बनती जा रही है क्योंकि सरकार ने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी है, लगातार खाद, बीज व किटनाशाको के रेट बढ़ाये जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र के बजट में हर बार कटौती की जा रही है, जिसके कारण 2 लाख 96 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं. लेकिन दूसरी तरफ रक्षा बजट बढाया जा रहा. देश का सैनिकीकरण किया जा रहा है. करोड़ों किसानों के लिए कुछ करोड़ रुपयों का, तो मात्र कुछ लाख की सेना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया जाता है. यूपीए सरकार साम्राज्यवाद परस्त एलपीजी नीतियों को लागू कर रही है, जनता उसके विरोध में उतरने से उस पर फासीवादी दमन चलाया जा रहा है.राहुल गांधी का गैस का नाटक सबके सामने है. पहले 12 सिलेंडर ही दिये जाते थे, लेकिन 2013 बजट में घटा कर 6 सिलेंडर कर दिये गए. अभी चुनावों को देखते हुए फिर 12 सिलेंडर दिये जाने की घोषणा की गयी है. इसके लिए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी 'प्रधानमंत्री पर गर्जे'! यह केवल जनता को लुभाने का नाटक है.

भाजपा आज एक फासीवादी हत्यारे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद्वार घोषित कर जर्रा भी नहीं शरमा रही है. वह प्रचार कर रही है कि वह गुजरात मॉडल की तर्ज पर देश का विकास करेगी. गुजरात में 2000 से ज्यादा मुस्लमानों का कत्ल बीजेपी, आरएसएस, बजरंगदल जैसे संगठनों द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया. गुजरात और ओड़िशा में भाजपा व अन्य भगवा आतंकवादी संगठनों द्वारा इसाइयों, दलितों पर हमले किये गए. नवीन पटनायक की भी इसमें मूकसहमति थी. क्या यही गुजरात मॉडल है. गुजरात में जनता का नहीं बल्कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे पूंजीपतियों का विकास हुआ है. हजारों किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है.जनप्रतिरोध की आवाज का कोई समाचार नहीं बनने दिया जाता. अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनता है इस से कोई बुनियादी बदलाव भारत में नहीं आने वाला. दरअसल मनमोहन सिंग 1991 से जिन नीतियों को आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी गुजरात में उन्हीं नीतियों को लागू किया है. वह नीतियां है उदारीकरण, नीजिकरण व भूमंडलीकरण की यानि देश की तमाम संपत्ति को दलाल पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों को सौंप दो. इन नीतियों को लागू करने में कांग्रेस व भाजापा के मोदी में कोई फर्क नहीं है.

नरेंद्र मोदी एक और नारा उच्छाल रहा है कि वह काले धन को स्विस बैंकों से वापस लायेगा. क्या जब बीजेपी सरकार में थी, तब उसे स्विस बैंकों का पता-ठीकाना नहीं मालूम था? गुजरात के नेताओं, पूंजीपतियों का काला धन क्यों अब तक वह स्विस बैंकों से नहीं निकलवाया जबकि 15 साल हो गये उसे मुख्यमंत्री बने. इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं लेकिन उसकी पार्टी भी,10 सालों तक इस मामले पर कुछ भी नहीं की. यह चुनावी स्टंट मात्र है.

'गुजरात मॉडल', स्विस बैंकों से पैसा लाने और रक्षा पर खर्च बढ़ाने के नारे सिर्फ मध्यम वर्ग को आर्किषत करने वाले हैं, इस से देश की 90 प्रतिशत मजदूर-किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला.

हर चुनावी मौसम की तरह इस बार भी तीसरा फ्रंट के रुप में सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एआईडीएमके आदि संभावनायें तलाश रहे हैं. तीसरा फ्रंट भी कांग्रेस–भाजपा से अलग हो ऐसी कोई बात नहीं है. सब पार्टियां अवसरवादी हैं. कौन कब पल्टी मारें कोई कह नहीं सकता. तमाम चुनावी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है देश को कैसे लूटना है, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है. अपने-अपने राज्यों में ये तमाम पार्टियां विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं, लूटवाती हैं.

नवीन पटनायक की बीजू जनता दल 15 सालों से ओड़िशा में फासीवादी सत्ता चला रही है. इस ने दलाल पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों से समझौते कर सारी खनिज व वन संपदा को बेच दिया है. ओड़िशा को व ओड़िशा की जनता को पूरी तरह कंगाल बनाकर भूखमरी, गरीबी की दलदल में धकेल दिया है. विस्थापन, पलायन व भूखमरी ओड़िशा की पहचान बन गयी है.

अब की बार भारतीय चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी मीडिया में छाई हुई है. केजरीवाल अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ योध्दा के रुप में

पेश कर रहा है. अरविंद केजरीवाल भ्रष्टचार के खिलाफ जनता के गुस्से को भुना कर सत्ता में आना चाहता है. अरविंद केजरीवाल इस व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता. जिस संसद की नीव भ्रष्टाचार, लूट व शोषण पर टीकी हो वह उस पर कैसे भ्रष्टाचारविहीन इमारत का निर्माण कसर सकता? अरविंद केजरीवाल जो मीठे सपने दिखा रहा है, जो वायदे कर रहा है वह छलावा है, उस धोखे में जनता को नहीं फंसना चाहिए. आने वाले समय में पता लग जाये गा कि वह साम्राज्यवाद, सामंतवाद व बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करेगा या जनता के हित में!

संसदीय चुनावों से जनता का विश्वास धीरे-धीरे घटता गया. जनता ने चुनावों में भाग लेना ही छोड़ दिया. परिणाम स्वरुप पचास प्रतिशत से भी कम मतदान होता था. इस लोकतंत्र के मुखोटे को बचाने के लिए, और कुछ प्रगतिशील शक्तियां जीते हुए उम्मीद्वार को वापस बुलाने के अधिकार के लिए लड़ रही थीं. वहीं संघर्षरत इलाकों की जनता ने तो सिरे से ही इन चुनावों को खारिज कर चुनावों के बहिष्कार का नारा बुलंद किया हुआ है. जनता के उठते विश्वास को फिर से कायम करने के लिए, जनता की चुनावों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए नोटा बटन को सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने मशीनों में लगाया है. नोटा बटन पूरी तरह से शक्तिहीन है क्योंकि जीतने वाले उम्मीद्वार से ज्यादा वोट भी नोटा बटन पर गिर जायें तो वहां के चुनाव रद्द नहीं होते न ही वह उम्मीद्वार हारा हुआ माना जाता. कुल मिलाकर यह जनता को गुमराह करने वाला बटन है और कुछ नहीं!

देश की मुक्ति के लिए, अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए माओवादी पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता, खासकर आदिवासी जनता संघर्ष कर रही है. इस संघर्ष की बदौलत उसने कई विदेशी व बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों की लूट को रोक दिया है. बैलाडिला से लोह अयस्क लूट कर लेजाया जा रहा है, रावघाट खदान खोलने के लिए, हजारों बीएसएफ को लगाकर रेल लाईन का निर्माण किया जा रहा है. पोस्को, टाटा, बिरला, वेदांता, अंबानी, जिंदल आदि के साथ केंद्र व रज्य सरकारों ने कई एमओयू साइन कर रखे हैं. माओवादी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गयी है, क्योंकि उनकी लूट नहीं चलने देती. इसलिए शोषक-शासक वर्गों ने आपरेशन ग्रीनहंट की दमन शुरुआत की कांग्रेस हो या बजेपी, जनता दल हो या एनसीपी, ममता बैनर्जी हो या माकपा-भाकपा सभी ग्रीनहंट के नाम पर देश की अपनी ही जनता पर युध्द छेड़ने के लिए एकजुट हैं. कोई भी पार्टी जो चुनावों में खड़ी है इस अन्यायपूर्ण युध्द का विरोध नहीं करती. अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए अपने ही देश की सेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों को उतारा जा रहा है, सैकड़ों गांव तबाह करा दिये जा चुके हैं, दर्जनों महिलाओं से बलत्कार किये जा चुके हैं, एड़समेट्टा, सार्केगुड़ा, से लेकर नियमगिरी, लांजीगढ़, गंदमर्धन, लालगढ़, सोनाबेड़ा, मैनपुर, उदंती सब जगह दमन का तांडव जारी है.

अगर देश को सही जनवाद, मुक्ति और विकास चाहिए तो वह दंडकारण्य, बिहार-झारखंड के रास्ते से ही हो सकता है. माओवादी पार्टी जनता से वायदा करती है कि नवजनवादी क्रांति की सफलता के बाद वह विदेशी कपंनियों, बड़े पूंजीपतियों की सारी संपत्ति छीन कर देश की जनता की संपत्ति घोषित कर देगी. विदेशों के सारे कर्जे रद्द कर देगी और हर जोतने वाले को जमीन की व्यवस्था करेगी.

हमारा आव्हान है कि चुनावी वायदों की मीठी गोली में छीपे जहर को पहचानिये, देश के गद्दारों, देश को बेच कर खाने वालों को अपने इलाके से मार भागाइये.

इसलिए मजदूर-किसानों, छात्र-बुध्दिजीवियों, दुकानदार-कर्मचारियों, महिलाओं सहित देश की सारी जनता से हमारी पार्टी आव्हान करती है कि इन झूठे लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करे और देश की मुक्ति के लिए, देश को साम्राज्यवाद, समांतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के पंजों से छुड़वाने के लिए माओवाद की राह चुने. पीएलजीए में भर्ती होकर नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करे!

- ☞ घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, देश को बर्बाद करने वाला, देश की जनता पर युध्द लादने वाली कांग्रेस पार्टी को मार भगाओ!
- ☞ भगवा आतंकवादियों के दंगाई गुजरात मॉडल का विरोध करो, स्विस बैंकों से वापस काला धन लाने का वादा मात्र छलावा है!
- ☞ हजारों मुस्लमानों, इसाइयों, दलित, आदिवासियों पर हमले कर हत्याएं, लूटपाट, अत्याचार, आगजनी करने वाली फासीवादी, भगवा आतंकवादी भाजपा को मार भागाओ!
- ☞ चुनाव एक तमाशा है - संघर्ष ही एक आशा है!
- ☞ जनता की मौलिक व बुनियादी समस्याओं का समाधान केवल नव जनवादी क्रांति से ही संभव है -
  झूठे लोकसभा या विधानसभा चुनावों से नहीं!
- ☞ सच्चे जनवाद के लिए दंडकारण्य-बिहार-झारखंड द्वारा दिखाई गयी राह चुनो!

ओड़िशा राज्य कमेटी
भाकपा (माओवादी

क्यों बहिष्कार चुनावों का ?

पिछले 65 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों ने देश का कितना बेड़ा गर्क कर दिया है नीचे दिए जा आंकड़ो और तथ्यों से समझें, और ये भी समझे क्यों हमें चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए

देश की हालात

1947 से लेकर अब तब बड़े बांधों, बड़ी परियोजनाओं के नाम पर 6 करोड़ जनता को अपने घरों, खेत-खलिहानों से उजाड़ दिया जा चुका है. उजाड़े गए 75 प्रतिशत लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया. विस्थापितों में हर छटवां नागरिक आदिवासी है. अब तक 250 लाख हेक्टेयर जमीन को इन विनाश परियोजनाओं के मुंह में धकेल दिया गया है.

देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को कर्जों की दल-दल और विदेशी कंपनियों के हार्यब्रिड बीजों, रसायनिक खादों के चक्कर में फसा दिया गया जिस कारण केवल 1997 से अब तक 2 लाख 54 हजार

देश में विदेशी कंपनियों व बड़े पूंजीपतियों को स्पेशल इक्नॉमिक जोन (एसईजेड) बनाने के लिए किसानों व आदिवासियों की 41 हजार 700 हेक्टेयर जमीन दे दी गयी है. इस जमीन पर 576 एसईजेड बनेंगे. एसईजेड ऐसा विशेष उद्योगिक क्षेत्र होता है जहां भारत के संविधान का एक कानून भी नहीं लागू होता, और सरकार उसे बिजली, पानी, टेक्स पर भारी छूट प्रदान करती है.

एशियन बैंक के सर्वे के अनुसार भारत में 62 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है.

भारत के दलाल राजनेताओं, बड़े पूंजीपतियों व जमींदारों ने विदेशो में काला धन 50 अरब डालर यानि 27,500,000,000,000 रु, जमा करवा रखे हैं. अगर यह धन भारत की गरीब जनता के ऊपर खर्च

किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी. हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है. 1997 से 2007 तक 1 लाख 82 हजार 936 किसानों ने आत्महत्या की. पहले स्थानीय बीज 7 से 9 रुपये किलो मिलता था वह अब 1100 रुपये किलो तक हो गया है.

1997 से 2007 के बीच 1.83 लाख टन गेंहूं, 6.63 लाख टन चावल, 2.2 लाख टन धान और लाखों टन मक्का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ गया. कुल मिलाकर 11.700 लाख टन अनाज सड़ने की बात कृषि मंत्री शरदपवार ने भी स्वीकारी थी. इतना अनाज 6 लाख लोगों का पेट भर सकता था.

देश की 18 करोड़ जनता झुग्गी-झोपड़ियों में और 18 करोड़ जनता फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर है.

गांव में मात्र 20 रुपये और शहरों में मात्र 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 77 प्रतिशत जनता अपने उपर खर्च कर पाती है. इतने पैसे में खाना ही पूरा नहीं हो पाता है तो दवाई, पढ़ाई, बिजली, मकान जैसी सुविधाओं की तो बात ही नहीं की जा सकती.

दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं. देश के 60 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है और 10 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने पर मजबूर हैं. 75 प्रतिशत माताओं को पोषक खाना नहीं मिल पाता.

भारत की 85 प्रतिशत संपत्ति पर मात्र 10 प्रतिशत जमींदार, पूंजीपति कब्जा जमा कर बैठें हैं जबकि 65 प्रतिशत किसानों के पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है.

किया जाये तो काफी हद तक गरीबी को दूर किया जा सकता है. एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं.

देश में 6 करोड़ से ज्यादा पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं.

देश में नक्सलबाड़ी से लेकर अब तक 14000 के आसपास आम क्रांतिकारी जनता, नौजवानों सहित माओवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या झूठी मुठभेड़ों, हमलों में इस भारतीय लोकतंत्र ने की है.

कश्मीर के 70 हजार नौजवानों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर गायब कर दिया गया. सैकड़ों महिलाओं से बलात्कार किये गए. गायब किये गए नौजवानों का कोई आता पता नहीं है, हर रोज गुमनाम, गुप्त कब्रे कश्मीर घाटी में पाई जाती हैं. उत्तपूर्व के रज्य मणिपुर, आसाम, अरुणांचलप्रदेश, त्रिपुरा आदि में भी यही मौत का खोल सैनिक व अर्ध सैनिक बलों द्वारा खोला जा रहा है.

गुजरात में 2000 से ज्यादा मुस्लमानों का कत्ल बीजेपी, आरएसएस, बजरंगदल जैसे संगठनों द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया. पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुजफरनगर जिले में भी समाजवादी पार्टी व बिजेपी ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए हिंदू-मुस्लमान के दंगे करवाये. ओड़िशा के कंधमाल, गंजम-गजपति जिलों में भी भाजपा व नवीन पटनायक ने इसाईयों पर हमलों को अंजाम दिया. 1984 में कांग्रेस ने दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल किया था, और अमृतसर के सिख गुरुद्वारे में आपरेशन बलुस्टार चलाकर भी हजारों सिख नौजवानों का नरसंहार किया था. कुल मिलाकर देश में अल्पसंख्यक और दलित जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं.

माओवादी क्यों चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हैं -

क्यांकि यह व्यवस्था गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है. राशनकार्ड बनवाने से लेकर हवाई जहाज खरीदने तक के तमाम काम बिना दलालों के नहीं होते. मंत्री से संतरी

तक और सेना से पुलिस तक, चपरासी से कलेक्टर तक सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं. टाटा, बिरला, रिलायंस, मित्तल सब रिश्वत देने के आरोपों में मुकद्दमों का सामना कर रहे हैं.

क्योंकि इस व्यवस्था में महिलाओं को पांव की जूती समझा जाता है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है. हर तीन मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है. सेना व अर्ध सैनिक बल संघर्षरत इलाकों में बलात्कार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.

क्योंकि सरकार को इंसानों से प्यार नहीं, जानवरों से प्यार है. टाईगर रिवर्ज के नाम पर पीढ़ियों से निवास करती आ रही जनता को उजाड़ा जा रहा है. सोनाबेड़ा-सीतानदी-उदंती के किसान-आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटक रही है.

क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलिकोम, खदान, बिजली आदि सब क्षेत्रों को निजी और विदेशी हाथों में बेचा जा रहा है. हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है. शिक्षा-स्वास्थ्य को बाजार बना दिया गया है, गरीब किसान, कर्मचारी, मजदूर का बेटा उच्च शिक्षा के सपने मात्र देख सकता है.

क्योंकि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मंहगाई को आसमान पर चढ़ाया जा रहा है. गरीबों, कर्मचारियों, पैदा करने वाले किसानों की थालियों से भी प्याज, आलू, दाल, तेल आदि गायब होते जा रहे हैं. जब किसान से ये तमाम चीजें खरीदी जाती हैं तो इनके भाव सस्ते होते हैं और जैसे ही बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों के गोदामों में पहुंचते हैं तो इनको बेचने वाला किसान खरीदने के लायक भी नहीं रहता.

क्योंकि सारी पार्टियां बजेपी हो या कांग्रेस, जनता दल हो या एनसीपी, ममता बैनर्जी हो या माकपा-भाकपा सभी ग्रीनहंट के नाम पर देश की अपनी ही जनता पर युध्द छेड़ने के लिए एकजुट हैं. कोई भी पार्टी जो चुनावों में खड़ी है इस अन्यायपूर्ण युध्द का विरोध नहीं करती. अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए अपने ही देश की सेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों को उतारा जा रहा है, सैकड़ों गांव तबाह करा दिये जा चुके हैं, दर्जनों महिलाओं से बलात्कार किये जा चुके हैं, एड़समेट्टा, सारकेंगुड़ा, से लेकर नियमगिरी, लालगढ़, सोनाबेड़ा सब जगह दमन का तांडव जारी है.

इसलिए देश की तमाम जनता से हमारी पार्टी आव्हान करती है कि इन झूठे लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करे और देश की मुक्ति के लिए, देश को साम्राज्यवाद, समांतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के पंजों से छुड़वाने के लिए माओवाद की राह चुने. पीएलजीए में भर्ती होकर नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करे.

भारत में नवजनवादी क्रांति के बाद हमारी सरकार क्या करेगी ?

वर्तमान लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ माओवादी पार्टी का विकास का 25 सुत्री वैकल्पिक मॉडल

जनता के बड़े दुश्मनों के प्रति नीति

1) यह साम्राज्यवादी पूँजी के सभी बैंकों, व्यावसायिक उद्यमों तथा कम्पनियों को जब्त करेगा और सभी साम्राज्यवादी कर्जों को रद्द करेगा। यह साम्राज्यवादी देशों के साथ की गयी सभी असमान सन्धियों और समझौतों को भी रद्द करेगा।

2) यह राज्य दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग के सभी उद्योगों, उनकी पूँजी और चल-अचल सम्पत्ति को जब्त करेगा। पूँजी को नियन्त्रित करने के उसूल के आधार पर इस राज्य को सभी इजारेदार उद्योगों और व्यापारों का प्राधिकार और प्रशासन अपने हाथ में ले लेना होगा। नव जनवादी राज्य अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ति को हाथ नहीं लगायेगा और ऐसे पूँजीवादी उत्पादन के विकास को बाधित नहीं करेगा जिसके पास सार्वजनिक जीवन को नियन्त्रित करने की शक्ति न हो।

3) यह जमींदारों और धार्मिक संस्थाओं की सम्पूर्ण जमीन को जब्त करेगा और उसे 'जमीन जोतने वालों की' के नारे के आधार पर भूमिहीन-गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों में बाँट देगा। यह भूमि पर महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करेगा। यह इन वर्गों के साथ-साथ मध्यम किसानों तथा अन्य मेहनतकशों के सभी कर्जों को रद्द करेगा। यह कृषि के विकास के लिए सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पाद के लिए लाभदायक कीमतों को सुनिश्चित करेगा और जहाँ भी संभव हो, कृषि-सहकारिता के विकास को बढ़ावा देगा तथा उसे प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार कृषि को नींव के रूप में रखते हुए यह एक मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ेगा। साथ ही यह सूदखोरों, महाजनों व व्यापारियों के शोषण को समाप्त करेगा, जनता को जरूरत की पूँजी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा और व्यापार तथा व्यवसाय को अपने नियन्त्रण में लेगा।

औद्योगिक व कृषि नीति

4) देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को विकसित करते हुए यह पर्यावरण के सन्तुलन और पर्यावरण के नियमों को लागू करना सुनिश्चित करेगा।
5) यह लघु उद्योगों की सुरक्षा करेगा, मँझोले उद्योगों, यानी राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के उद्योग-धन्धों को सीमित व नियन्त्रित करेगा, सहकारिता के विकास द्वारा हस्तकला तथा कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करेगा और हस्तकला शिल्पियों, दस्तकारों व कारीगरों की स्थिति में सुधार लायेगा।
6) यह तमाम भारी करों व विभिन्न अदायगियों को खत्म करेगा, मौजूदा कर-प्रणाली को रद्द कर देगा और एक सुव्यवस्थित, सरल व प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू करेगा।
7) यह छः घंटे के कार्य-दिवस को लागू करेगा, मजदूरी-दर को बढ़ायेगा, ठेकेदार मजदूरी की व्यवस्था तथा बाल-श्रम का खात्मा करेगा, सामाजिक सुरक्षा व सुरक्षित कार्य-परिस्थिति मुहैया करायेगा और समान काम के लिए समान मजदूरी की गारण्टी देकर लिंग के आधार पर मजदूरी में सभी असमानताओं को खत्म करेगा।
8) यह काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा और बेरोजगारी को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह राज्य बेकारी भत्ता तथा सामाजिक बीमा लागू करेगा और लोगों के लिए जीवन-यापन की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करेगा।

जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए नीति

9) यह 'जमीन जोतने वाले की' के आधार पर जमीन कर बँटवारा करके और गरीब किसानों तथा भूमिहीन किसानों (जिनका बड़ा हिस्सा दलित, आदिवासी तथा दूसरी उत्पीड़ित जातियाँ होंगी)के नेतृत्व वाली नयी सत्ता के सहारे जाति व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह जातिगत भेदभाव तथा असमानता को खत्म करेगा और समग्र रूप से छुआछूत तथा जातिप्रथा का सम्पूर्ण विनाश करने की ओर बढ़ेगा। तब तक यह दलितों व सामाजिक रूप से सभी उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा।

महिला व बाल विकास नीति

10) यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और पुरुष-प्रधानता तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा। यह राज्य महिलाओं को घरेलू कामकाज की बेड़ियों से मुक्त करायेगा और सामाजिक उत्पादन तथा अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह सार्वजनिक कपड़ा धुलाई स्थल, शिशु-गृहों और सार्वजनिक रसोईघरों को चलायेगा। यह सम्पत्ति पर महिलाओं के समान अधिकार की भी गारण्टी करेगा। महिलाओं जिन असमानताओं का सामना करती हैं उनको तेजी से खत्म करने के लिए यह विशेष नीतियों को बढ़ावा देगा और महिलाओं की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह राज्य वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करेगा।
11) यह राज्य सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि बच्चों को एक जनवादी माहौल मिले।

आदिवासी समुदायों के प्रति नीति

12) यह सभी आदिवासी समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएँ सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियाँ लागू करेगा।

राष्ट्रीयताओं के प्रति नीति

13) यह राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उनकी समान मर्यादा के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। यह भारत के लोक जनवादी संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक महासंघ की स्थापना करेगा।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नीति

14) धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और धर्म-आधारित सभी सामाजिक असमानताओं को यह राज्य समाप्त करेगा। साथ ही यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह राज्य की वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की गारण्टी करेगा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलअन्दाजी को समाप्त करेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारण्टी करेगा। साथ ही यह कुसंस्कारों व अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा और सभी किस्म के धार्मिक रूढ़िवाद का विरोध करेगा।

सांस्कृतिक नीति

15) यह क्षरणशील, सामन्ती, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी संस्कृति के स्थान पर क्रान्तिकारी नव जनवादी संस्कृति को स्थापित करेगा, इस आधार पर

समाजवादी संस्कृति का मार्ग प्रशस्त करते हुए साम्यवादी संस्कृति को आत्मसात करने की दिशा में अभियान जारी रखेगा।

शिक्षा नीति

16) यह वर्तमान शिक्षा–प्रणाली का उन्मूलन करेगा और इसकी जगह जनवादी भारत की जरूरतों के अनुसार एक वैज्ञानिक, जनवादी, समाजवादी व सर्वसुलभ जनशिक्षा–प्रणाली शुरू करेगा जो शिक्षा को उत्पादन से जोड़ेगी।

17) यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं की भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्रभाषा या सम्पर्क–भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा।

राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा

18) यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर बढ़ेगा। यह राष्ट्रीयताओं के बीच नदी जल बँटवारा, सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आम सहमति से हल करेगा।

सत्ता का स्वरुप व चुनाव

19) यह नया राज्य सभी स्तरों पर जनता के जनवादी संविधान के अनुसार और उसके आधार पर क्रान्तिकारी जन कमेटियों और सभी स्तरों पर जन संचालन परिषदों के द्वारा जनता की राजनीतिक सत्ता स्थापित करेगा। कट्टर प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष का हो चुका/चुकी हो, सभी स्तरों पर चुनने व चुने जाने का और निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा। यह राज्य सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार, इकत्रित होने, संगठित होने और हड़ताल व प्रदर्शन करने के अधिकारों जैसे जनवादी अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। यह राजसत्ता पर जनता के नियन्त्रण के अधिकार को सुनिश्चित करेगा और इस अधिकार को घटाने की हर कोशिश का विरोध करेगा।

न्यायकि प्रणाली

20) यह एक प्रगतिशील, जनवादी और जनपक्षीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को सुधारने के उद्देश्य से न्यायपूर्ण विधि प्रणाली व व्यवस्था लागू करेगा।

देश की रक्षा नीति

21) यह देश की सुरक्षा के लिए जनता को हथियारबन्द करेगा। यह शहीदों और जन मुक्ति सेना के सैनिकों के परिवारों का जरूरत के मुताबिक पुनर्वास करेगा और उन्हें भूमि भी उपलब्ध करायेगा।

विकलांगों के प्रति नीति

22) यह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मानसिक रूप से वंचित व्यक्तियों, बुजुर्गों, अनाथों, किन्नरों तथा असमर्थताओं से पीड़ित अन्यान्य लोगों को उपयुक्त आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा और एक स्वस्थ सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण मुहैया करायेगा। साथ ही यह सभी लोगों के लिए, खास कर मजदूरों, किसानों तथा अन्य मेहनतकश जनता के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा मुफ्त चिकित्सा सुनिश्चित करनेवाली एक जनमुखी चिकित्सा–प्रणाली को लागू करेगा।

विदेश नीति

23) यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शान्तिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा और उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्ययहार नहीं करेगा।

24) विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ सम्बन्धों में यह राज्य निम्न पाँच सिद्धान्तों का पालन करेगा – क्षेत्रीय अखण्डता व सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक–दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बराबरी एवं परस्पर हित तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व।

25) यह लोक जनवादी राज्य अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रों के साथ एकता स्थापित करेगा और साम्राज्यवादी युद्ध तथा आक्रमण, जोर–जबरदस्ती, विध्वंस, दखलन्दाजी आदि का विरोध करेगा और पूँजीवाद, साम्राज्यवाद तथा प्रतिक्रियावाद के खिलाफ पूरी दुनिया में चल रहे क्रान्तिकारी संघर्षों और युद्धों, खास कर विभिन्न माओवादी क्रान्तिकारी शक्तियों के नेतृत्व में चल रहे संघर्षों का हर सम्भव तरीके से समर्थन व सहयोग करेगा। क्रान्ति में जीत के बाद नव जनवादी भारत और बाद में समाजवादी भारत विश्व समाजवादी क्रान्ति की विजय को नजदीक लाने के लिए एक आधार क्षेत्र का काम करेगा। इस उपमहाद्वीप की जनता के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बन्धों को देखते हुए यह खास कर दक्षिण एशिया की क्रान्तिकारी तथा माओवादी शक्तियों और उनके संघर्षों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करेगा।

जीते कोई - सरकार बनेगी साम्राज्यवाद परस्त

बात 1990 की है, फ्रांस के एक दैनिक समाचार पत्र 'लमोन फ्रांस' में खबर छपी थी कि भारत में 1991 में सरकार किसी की भी बने अगले वित्तमंत्री मनमोहन सिंग बनेंगे. उस समय मनमोहन सिंग को राजनेता के रुप में कोई नहीं जानता था. मनमोहन सिंग एक प्रोफेसर थे. उसने वित्तमंत्री बनने से पहले 10 साल तक वर्ल्ड बैंक अमेरीका की सेवा की थी. वर्ल्ड बैंक ने भारत को बहुत सारा कर्ज दिया हुआ था. उस कर्ज को वापस लेने के लिए उसे वित्तमंत्री बनवाया गया था. मजेदार बात यह है कि उस समय मनमोहन सिंग ने भारत सरकार से मात्र 1रुपया 25 पैसा वेतन लिया था. इतने भारी-भरकम वेतन को ठोकर मारकर वह क्यों इतने कम वेतन पर वित्तमंत्री बनने के लिए तैयार हो गया था? समझने के लिए वेद -पुराण पढ़ने की जरुरत नहीं है. ऐसा ही हुआ दूसरे वित्तमंत्री चिंदबरम के लिए. उसे भी विश्व बैंक ने बनवाया. जब वह इस्तीफा देने लगा तो विश्व बैंक ने ही उसे रुकवाया था. इतना ही नहीं चिदंबरम के बारे में तो स्पष्ट हो चुका है कि वह वेदांता नामक कंपनी का बड़ा चहेता है और काफी पैसा उसका लगा हुआ है.

पहले साम्राज्यवादी यह काम लुकाछुपी के साथ करते थे. अब तो सीधा भारतीय राजनीति में हस्तेक्षप करके चुनावी परिणामों तक को प्रभावित कर रहे हैं. निरा राडिया टेप कांड से स्पष्ट हो चुका है कि केबिनेट के तमाम मंत्रियों को बनवाने के लिए टाटा, बिड़ला, रिलांयस, जिंदल आदि करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके लिए लॉबिंग करती हैं. हाल ही के समाचार देखें तो स्पष्ट दिखता है - अमेरीकी साम्राज्यवाद सहित तमाम कार्पोरेट घराने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान कर चल रहे हैं. गुजरात में मुस्लमानों के नरसंहार के विरोध में अमेरीका ने अब तक नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करने का नाटक किया था, उसे दस साल तक अमेरीका में प्रवेश तक नहीं करने दिया लेकिन अब अमेरीका विदेश मंत्रालय की नैन्सी पावेल खुद आकर गुजरात की राजधानी में उसे मुलाकात कर रही है. उसकी तरीफ के पुल बांध रही है.

और सोचने का विषय यह भी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इंक्मटेक्स डिर्पाटमेंट के कमीश्नर का बड़ा पद छोड़कर क्यों अरविंद केजरीवाल राजनीति में झक मार रहा है. क्यों उसने एनजीओ यानि गैर सरकारी संगठन चलाने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया. ऐसे गैर सरकारी संगठनों को साम्राज्यवादी देश अमेरीका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि बड़ी आर्थिक मदद देकर चलाते हैं. तो अरविंद किस के लिए काम करेगा? और अभी बजट पर टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मनमोहन सिंग साम्राज्यवाद प्रस्त नीतियों को अपना समर्थन भी दे दिया है. केजरीवाल भी वालस्ट्रिट समर्थक नीतियों को जारी रखेगा.

साम्राज्यवाद बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. उसे निकलने के लिए कच्चा माल भारत में है. भारत का बड़ा बजार भी उसे लुभाता है. और भारत भी बड़े संकट से गुजर रहा है. किसी को भी कांग्रेस, भाजपा पर विश्वास नहीं है. साम्राज्यवाद फिर यहां पर व्यक्ति केंद्रीत राजनीति को बढ़ावा दे रहा है. भारत के चुनाव को राहुल, मोदी और केजरीवाल के बीच का चुनाव बना रहा है. पार्टियों पर से जनता का विश्वास उठ चुका है. साम्राज्यवाद समझ चुका है. मनमोहन अब किसी को मोहने के काबिल नहीं रहा, भाजपा केवल मुस्लमानों के खिलाफ बोल कर संसद में बहुमत नहीं पा सकती, क्षेत्रीय पार्टियां किसी के भी पीछे लगने के लिए तैयार हैं, इसलिए साम्राज्यवाद मोदी, केजरीवाल के सिक्के को चलाना चाहता है. खैर सरकार किसी की बने अमेरीका का सहित तमाम पूंजीपतियों और कंपनियों के हितों को कोई नुकसान नहीं होने वाला. उनके हित किसी भी पार्टी की सरकार मे ं सुरक्षित हैं.

जो कोई व्यक्ति क्रांतिकारी जनता का साथ देता है, वह एक क्रांतिकारी है. जो कोई व्यक्ति साम्राज्यवाद, सामंतवाद, और नौकरशाह पूंजीवाद का साथ देता है, वह एक प्रतिक्रांतिकारी है. जो कोई व्यक्ति केवल कथनी में ही क्रांतिकारी जनता का साथ देता है, किंतु करनी में ऐसा नहीं करता, वह केवल जबानी जमा खर्च करने वाला क्रांतिकारी है. जोद कोई व्यक्ति कथनी और करनी दोनों में क्रातिकारी जनता का साथ देता है वही एक सच्चा क्रांतिकारी है.

ओड़िशा राज्य को बेच खाया नवीन पटनायक सरकार ने !

ओड़िशा को बचाने के लिए विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो - माओवाद की राह चुनो !

अगले ओड़िशा विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं. नवीन पटनायक सरकार पूरे गाजे-बाजे के साथ चुनाव में उतर गयी है और ओड़िशा के विकास के नाम पर वोट मांग रही है. लेकिन सवाल उठता है कि पिछले पंद्रह सालों में नवीन बाबू की सरकार में किसका विकास हुआ है? आज भी ओड़िशा गरीबी और भुखमरी के लिए पूरे देश में बदनाम हैं, लोगों ने आम की गुठलियां खाकर इसी राज्य में जान दी हैं क्योंकि अनाज नहीं मिलता! ओड़िशा में टाटा, रिलायंस, जिंदल, पोस्को, मित्तल, वेदांता, हिंडालको, स्टारलाईट, वेलस्पुन पावर एंड स्टील, नालको का विकास हुआ है. उन्होंने हजारों करोड़ रुपये यहां से कमाई कर अपनी कंपनियों की संख्या दुगनी कर ली है लेकिन ओड़िशा जनता को पहले से ही आधे पेट रहने पर मजबूर है और पिछले पंद्रह सालों में यह आधे से भी आधा रह गया है. नवीन पटनायक विदेशों में दौरे कर पूंजीपतियों को न्यौता देकर बुलाता है कि ओड़िशा में 5231 करोड़ टन लोह के भंडार हैं, जो देश के कुल भंडारों का 35 प्रतिशत है आइये ये आपके लिए ही है. राज्य में 27 किस्म की खदाने हैं जो अरबों करोड़ों रुपयों का उत्पादन करती है. लेकिन जनता के हिस्से उस में से कुछ भी नहीं आता. तो यह विकास किसका केवल बड़े पूंजीपतियों का ही विकास है बाकि जनता का केवल विनाश और विनाश है!

ओड़िशा में तमाम बड़ी-बड़ी विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शाखाएं हैं जो राज्य को दिन रात लुटने में लगी हुई हैं. इनमें मुख्य रुप से राउरकेला स्टिल प्लांट जो भारत में पहला इंटिग्रेटिड स्टिल प्लांट है ओर जर्मनी के साथ मिलकर बनाया गया है. उसके अलावा एचएएल (सोनाबेड़ा कोरापुट), एनएएल दामनजोड़ी आंगुल बड़े उद्योग हैं. स्टील, पावर, लोह, एलुमिनयम, रिफाइनिरी आदि क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी कंपनियों ने यहां पर निवेश कर रखा है और कुछ करने की तैयारी में हैं. दुनिया की टोप कंपनियां टाटा कंस्लटेनसि, महिंद्रा सत्यम, माइंड ट्री कंस्लटेनसि, प्राइसवाटरकूकर, इनफोसस की भी यहां पर इकाईयां हैं. आईबीएम, विपरों भी अपने सेंटर खोल रही हैं.

2005 में नालको कंपनी ने ओड़िशा में 51162 करोड़ रुपये कमाए जबकि टाटा स्टील ने 2044 करोड़ रुपये. लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकार को कुल मिलाकर माइनिंग क्षेत्र से मात्र 670 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. अगर 2005 का उत्पादन देखा जाये तो बॉक्साइट 4911739 टन, लोह 46063158 टन के साथ कुल खदान उत्पादन 127050389 टन था. सवाल उठता है कि अरबों करोड़ रुपये करने वाली कंपनियों से मात्र 670 करोड़ का कर वसूल किया गया तो बाकि का पैसा कहां गया नवीन पटनायक सरकार कितना खाई और पूंजीपति कितना. कुछ भी हो जनता को तो और गरीबी की खाई में धकेला जाता रहा है.

> क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में सैकड़ों गुप्त समझौते इन विदेशी व बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के साथ ओड़िशा सरकार ने कर रखे हैं. जो समझौते खुले रुप में हुए हैं उनकी लिस्ट नीचे दी जा रही है. नवीन पटनायक सरकार ने पंद्रह सालों में 172000 करोड़ रुपये के समझोते यानि एमओयू किये हैं. इन 49 कंपनियों में से 9 कंपनियां ही 70 प्रतिशत से ज्यादा पैसा लगाई हैं.

जिलावर लूट का हिसाब देखें तो पता चलता है जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है या फिर कमजोर है वहां पर बेतहाशा लूट हो रही है. उन जिलों को नवीन पटनायक सरकार ने बर्बाद कर दिया है. सबसे ज्यादा माइनिंग क्योंझर जिला 31 प्रतिशत, दूसरा सुंदरगढ़ 20 प्रतिशत, तीसरा झरसगुडा 8 प्रतिशत और चौथा कोरपुट जिला 7 प्रतिशत खनन उत्पादन हुआ है. यानि इनको दानवी कंपनियों ने एक तरह से पूरा खाली कर दिया है. जमीन को बर्बाद कर डाला है. अब बारी उन जिलों की है जो अभी तक जनता के आंदोलन के कारण इस बर्बादी से बचे हुए हैं मसलन कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नुवापाड़ा, बलांगिर, गंजाम आदि.

क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में सैकड़ों गुप्त समझौते इन विदेशी व बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के साथ ओड़िशा सरकार ने कर रखे हैं. जो समझौते खुले रुप में हुए हैं उनकी लिस्ट नीचे दी जा रही है. नवीन पटनायक सरकार ने पंद्रह सालों में 172000 करोड़ रुपये के समझोते यानि एमओयू किये हैं. इन 49 कंपनियों में से 9 कंपनियां ही 70 प्रतिशत से ज्यादा पैसा लगाई हैं.

इसलिए आने वाला समय ओड़िशा को और बर्बादी की तरफ धकेलने वाला है क्योंकि गंदमर्धन, जगतसिंगपुर, कलाहंडी, रायगढ आने वाले समय में इन कंपनियों के बड़े निशाने हैं. लाखों आदिवासी जनता को विस्थपन करने की तैयारियां चल रही हैं. इस झूठे विकास के नाम पर फिर हजारों घरों व लाखों एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया जायेगा. क्या ऐसा आदमी या ऐसी पार्टी फिर से सत्ता में आने के काबिल है? क्या आप ऐसे नेता को फिर वोट देंगे जिसने अपने राज्य को विदेशी व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों को बेच दिया है? क्या आप उसे फिर सत्ता में लाओगे जिसने हजारों हेक्टेयर जंगल को काट दिया है?

प्रिय जनता हम आपसे अपील करते हैं कि सोचो, समझो और चुनावों का बहिष्कार करो!

सबसे बड़ी दानवीय कंपनियां जो ओड़िशा को लूटने पर आतूर हैं!

क्र.	कंपनी का नाम	स्थान		उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष मिट्रीक टन में	पूंजी निवेश करोड़ रुपयों में	हस्ताक्षर की तारीख
1	मैसर्स टाटा स्टील लि.	कलिंगनगर इंडिस्ट्रीयल कांपलेक्स, डुबरी जाजपुर	पहला माडयूल	3.00	10,400.00	17.11.2004
			दूसरा माडयूल	3.00	5,000.00	
2	मैसर्स स्टारलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	पालसपंगा क्योंझर	फेज-1	3.4	9,782.00	15.10.2004
			फेज-2	1.7	2,720.00	
3	मैसर्स एस्सार स्टील ओडिशा लि. .	पारादीप		4.00	10,721.00	21.04.2005
4	मैसर्स पोस्को इंडिया प्राईवेट लि.	पारादीप		12.00	51,000.00	22.06.2005
5	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.	देवझाड़ क्योंझर और आयरन प्लांट अंगुल		6.00	13,135.02	3.11.2005
6	मैसर्स भुषण स्टील लि.	मेरामुंडालाई धेनकनाल		3.00	5,828.15	3.11.2005
7	मैसर्स वेलस्पुन पावर एंड स्टील लि.	टांगी चौदवार कट्टक व डुरपानी जाजपुर जिला में		3.00	6,103.80	11.10.2006
8	मैसर्स उत्तम गलवा स्टीले लि.	पलसपंगा क्योंझर		3.00	8,987.00	13.10.2006
9	मैसर्स अर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	पाटनल तहसिल क्योंझर	फेज-1	6.00	22,000.00	21.12.2006
			फेज-2	6.00	18,000.00	
10	मैसर्स एसएसएल एनर्जी लि.	नुहाटा बनर्तपाल के नजदिक अंगुल	फेज-1	3.00	4,339.00	21.12.2006
			फेज-2		4,270.00	
कुल				57.10	172,286	

कहां गया आदिवासियों और दलितों का पैसा?

ओड़िशा में 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या 81 लाख 45 हजार थी और दलितों की जनसंख्या थी 60 लाख 82 हजार 63. ओड़िशा सरकार का कहना है उसने 2009-10 में 1017 करोड़ रुपये आदिवासी व दलितों के विकास के लिए खर्च किये हैं. अगर पीछले चार सालों का बजट इस के अनुसार देखें तो 4 हजार 68 करोड़ रुपये हुआ. मतलब यह हुआ कि प्रति आदिवासी-दलित सरकार ने मात्र 28 हजार 593 रुपये खर्च किये. जबकि सबसे ज्यादा कंपनी, खदान आदिवासी व दलित इलाकों में ही है और सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को यहीं से प्राप्त होता है. लेकिन आदिवासी जनता पर खर्च करने की बजाये कहीं ओर खर्च किया जा रहा है या घोटालों में खाया जा रहा है.

इससे भी ज्यादा अश्चार्य में डाल देने वाली बात ये है कि आदिम जनजाति क्लयाण के लिए माईक्रो प्रोजेक्ट के तहत सोनाबेड़ा, नियमगिरी जैसे इलाकों में सरकार बता रही है कि उसने एक साल में 200 लाख रुपये 2038 परिवारों के विकास के लिए खर्च किये हैं. यानि प्रति परिवार 98135 रुपये सरकार ने खर्च किये. लेकिन जब जनता से पूछा जाये, या उन गांवों का जायजा लिया जाए तो तस्वीर सीसे की तरह साफ हो जायेगी. आदिवासी उप योजना के अंतर्गत वह पैसा बड़े-बड़े अधिकारियों की तोंद बढ़ाने के लिए काम आया है न कि आदिवासी जनता के विकास के लिए. नवीन पटनायक सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि वो पैसा कहां गया? किसने खाया?

साम्राज्यवादियों की नयी चाल - जनआक्रोश का सेफ्टी वाल्व - 'आप' के अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल से माओवादियों के दस सवाल

आम आदमी पार्टी (आप) इस पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को दिल्ली में हुआ था. मात्र एक साल पुरानी पार्टी राजनीति के धुरंधर बीजेपी और कांग्रेस को हरा कर दिल्ली में सरकार बनाकर सुर्खियाओं में छाई हुई है. कहा जा रहा है कि इसने भारत की राजनीति की बुनियाद को बदल दिया है. एक साफ राजनीति की शुरुआत हुई है. अरविंद केजरीवाल को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वह पूरी तरह से भारत का क्लयाण कर देगा. अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी कई लोग उसे देख रहे हैं.

वह राजनीति को किस तरह बदल देंगे इसकी असलियत तो उसके शपथ वाले दिन से ही समझ में आ जाती है - मीडिया ने बढ़ाचढ़ा कर उसकी शान के कसिदे कढ़े. मेट्रो रेल से शपथ ग्रहण समारोह में जाने, गाड़ी-बंगला न लेने पर सुर्खियां लगाई गयीं, लेकिन किसी भी अखबार व मीडिया ने यह नहीं बताया कि उसी दिन 26 दिसंबर को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास, उतर दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की 165 झुग्गियों वाली झोपड़ पट्टी पर बुलडोजर चला दिये गए. एक तरफ अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ ले रहा था दूसरी तरफ गरीब जनता की छोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा था. ध्यान देने की बात यह है कि वह आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है. कुछ दिन के बाद न केवल अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी ले ली बल्कि दस कमरों का बंगला व सरकारी सुरक्षा भी ली. नहीं तो अरविंद केजरीवाल कहता था कि मेरी सुरक्षा तो भगवान करेगा, और मैं दिल्ली से वीआईपी संस्कृति को खत्म कर दूंगा.

अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाया - 'राजनीति बदलेगी-देश बदलेगा' लेकिन हाल के घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि न तो वह देश बदल सकता न ही राजनीति, हां खुद जरुर घटिया बुर्जुआ राजनीतिक दल-दल में धस जायेगा. भारतीय संसद का इतिहास रहा है कि जो भी इसको इसे बदलने के नाम पर इस में गया वह खुद बदल गया है. इस में जाते ही पूंजीपतियों व जमींदारों के हितों की बात करने लग जाता है और बुर्जुआ राजनीति के नाटक का अभिनेता बन जाता है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में अपने बेटों की कसम उठाई थी कि वह कांग्रेस और भाजपा से समर्थन नहीं लेगा व न ही उनको समर्थन देगा. लेकिन हुआ क्या उसने जनता से पूछने के नाम का नाटक कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई. ताकि जनता को अपने काम का ट्रेलर दिखा सके. और लोकसभा चुनावों में उसका फायदा उठा सके. ठीक उसी स्क्रीपट के तहत उसने 14 फरवरी की रात को इस्तीफे की घोषणा कर दी. क्योंकि उसका अगला निशाना लोकसभा चुनाव है. इस इस्तीफे से वह

कांग्रेस और भाजपा दोनों को बदनाम कर सकता है, और जनता की सहानुभूति ले सकता है, यह चुनावी स्टंट मात्र है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुकेश अंबानी, मुरली देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने से कांग्रेस और भाजपा एक हो गयी हैं. वह भ्रष्टाचार के खिलाफ 1000 मुख्यमंत्री पद दांव पर लगाने के लिए तैयार है और जान देने के लिए भी तैयार है. यही अरविंद केजरीवाल थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि उसका लोकपाल कानून किसी को जेल में डालने के लिए नहीं है, बल्कि डराने के लिए है. इससे किसी को घबराने की जरुरत नहीं है. यानि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना कोई उसे जेल भेजने के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में वोट पाने का स्टंट मात्र है.

सभी को यह भी समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस भवन में बैठ रहा है

> सभी को यह भी समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस भवन में बैठ रहा है उसकी नींव कांग्रेस-भाजपा ने रखी थी. जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार, शोषण व लूट पर टिकी हो उस कुर्सी पर बैठ कर कौन मुख्यमंत्री देश को बदल सकता है. जब तक बुनियादी परिवर्तन इस व्यवस्था में नहीं हो जाता, पूरी तरह से लुटेरों के शासन को नहीं उखाड़ फैंका जाता तब तक कोई कुर्सी पर बैठे, कोई संसद में जाये वह भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता. अगर कोई कोशिश भी करेगा तो देश के जमींदार, पूंजीपति और साम्राज्यवादी उसे एक कदम भी नहीं चलने देंगे.

उसकी नींव कांग्रेस-भाजपा ने रखी थी. जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार, शोषण व लूट पर टिकी हो उस कुर्सी पर बैठ कर कौन मुख्यमंत्री देश को बदल सकता है. जब तक बुनियादी परिवर्तन इस व्यवस्था में नहीं हो जाता, पूरी तरह से लुटेरों के शासन को नहीं उखाड़ फैंका जाता तब तक कोई कुर्सी पर बैठे, कोई संसद में जाये वह भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता. अगर कोई कोशिश भी करेगा तो देश के जमींदार, पूंजीपति और साम्राज्यवादी उसे एक कदम भी नहीं चलने देंगे.

2012 में जनलोकपाल कानून बनाने की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने जंतर-मंतर पर अमरण अनशन किया था. अरविंद केजरीवाल भी उस आंदोलन का हिस्सा था. बाद में अन्ना हजारे से अलग होकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन कर राजनीति में उतरने का फैसला किया. इस पार्टी में ज्यादातर एनजीओ से जुड़े लोग हैं, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में एक एनजीओ चलाता था. 2000 में उसने परिवर्तन नाम का एनजीओ चलाना शुरु किया था. सुचना के अधिकार के लिए उसे साम्राज्यवादी देश द्वारा 2006 में रमन मैग्सेसे आवार्ड मिला, 2006 फरवरी में उसने इंक्मटेक्स विभाग के कमिश्नर पद से इस्तीफा दिया और पूरी तरह अपने एनजीओ को चलाने लग गया.

अरविंद केजरीवाल भारत में साम्राज्यवादियों द्वारा पोषित गैर सरकारी संगठनों की जीत है. अंततः साम्राज्यवादियों के पैसों, अनुदानों पर पलने वाले एनजीओ क्या करेंगे और क्या करते हैं इसका अनुभव बड़े पैमाने पर भारत की जनता को नहीं है. इसलिए उसके नारे लोगों को लुभा रहे हैं. दरअसल अरविंद केजरीवाल साम्राज्यवादियों द्वारा पोषित नौकरशाह है, जो अप्रत्यक्ष रुप से उनके हितों के लिए काम कर रहा है. पिछले 68 सालों में भारत की जनता तमाम राजनीतिक पार्टियों व संसद को खारिज कर चुकी है. देश में कभी भी सच्चे बहुमत की सरकार नहीं बनी है. भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी देश की जनता को हलाकान किये हुए है. दलाल पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों द्वारा शुरु की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीनों के अधिग्रहणों से जनता विस्थपित हो रही है. उनको अपने ही घरों से खदेड़ा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं. कुल मिलाकर न केवल आर्थिक रुप से बल्कि राजनीतिक रुप से भी भारत बड़े संकट में फसा हुआ है. साम्राज्यवादियों व भारत के शासक वर्गो को पता है कि अंततः **यह संकट क्रांति को जन्म देने वाला है. दलाल पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों ने समझ लिया है कि अब भारत की जनता को दबाए रखने के लिए, भ्रमाए रखने के लिए कांग्रेस व बीजेपी व अन्य पार्टियां नाकाफी हैं. इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादियों व दलाल पूंजीपतियों ने नई संतान को जन्म दिया है ताकि भारत की जनता के बढ़ते गुस्से व आक्रोश को क्रांति की तरफ जाने से रोका जा सके. इसलिए अरविंद केजरीवाल आक्रामक रुप में दिखते हुए अर्धसामंती-अर्ध औपनिवेशीक व्यवस्था के खिलाफ उबल रहे गुस्से को निकालने के लिए एक सेफ्टी वाल्व हैं.**

किसी एनजीओ को कार्पोट मीडिया द्वारा रातों-रात प्रसिध्द कर उसे इतने उंचे पहुंचाकर राजनीति सत्ता को कब्जाना यह साम्राज्यवादियों का भारत में एक नया प्रयोग है. इससे पहले साम्राज्यवादी ज्यादातर प्रचलित राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल करते थे या फिर उन देशों में जहां उन्होंने हमले किये और अप्रत्यक्ष शासन चलाना है जैसे अफगानिस्तान, इराक, लिबीया आदि में अपने पूराने कर्मचारियों, अधिकारियों को इस्तेमाल करते थे. या फिर उस देश में दंगे करवाकर बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं को अपनी लूट को टिकाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे. अफगानिस्तान में हामिद करजई, इराक में नुरी अल मलिकी, भारत में मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम भी अमेरिकी संस्थानों में काम कर चुके कर्मचारी ही हैं. शायद यह पहला मौका है जब किसी एनजीओ को उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक बनाकर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करवाया हो. अरविंद केजरीवाल एनजीओ के साथ-साथ भारत के शासक वर्ग नौकरशाह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं.

आम आदमी पार्टी हो या बिजेपी, कांग्रेस सभी की सभी इस लुटेरी व्यवस्था को बचाने व साम्राज्यवादियों की लूट को टिकाए रखने का ही काम करती हैं. अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी देश की राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती. देश में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, असली समस्या है जोतने वालों को जमीन चाहिए ताकि देश की 60 प्रतिशत भूमिहीन जनता सामाजिक व आर्थिक रुप से अपना विकास कर सके, गरीब किसान व मध्यम किसान को आज अपनी जमीन छीनने का खतरा मंडरा रहा है, बड़ी परियोजनाओं के लिए करोड़ो एकड़ जमीन अधिग्रहण होने वाली हैं, मजदूरों पर छंटनी की तलवार लटक रही है, लगातार कारखानों में मशीनों, तकनीकों को बढ़ा कर बेरोजगार किया जा रहा है. श्रम उत्पादकता बढ़ा कर श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है. छोटी कंपनियों को विदेशी व बड़ी कंपनियां निगल रही हैं, सरकार हर चीज को निजी हाथों यानि बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों को सौंप रही है जिस कारण से देश का पूंजीपति तबाह हो रहा है, छोटे उद्योग तबाह हो रहे हैं हमारी पार्टी पूछती है कि इन बुनियादि समस्याओं पर अरविंद केजरीवाल क्या सोचता है? क्या वह इन समस्याओं की जड़ जमींदारों, बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों को नष्ट कर सकता है, ताकि आमआदमी चैन की सांस ले सके और अपनी किस्मत खुद लिख सके! ऐसे ही बुनियादी प्रश्न हम उस पार्टी के लिए निचे दे रहे हैं, जनता से आव्हान करते हैं

कि जब आम आदमी पार्टी के नेता लोकसभा चुनावों के दौरान आपके गांव, शहर में आएं तो उनसे ये सवाल पूछें और पूछें कि क्या वह माओवादी पार्टी के 25 सुत्री व्यवस्था के वैकल्पिक मॉडल को लागू कर सकता है?

- अंग्रेज जाने के बाद भारत एक अर्ध–सामंती व अर्ध औपनिवेशिक देश बन गया. पहले केवल अंग्रेज लूटते थे, अभी अमेरीका सहित विभिन्न साम्राज्यवादी देश लूट रहे हैं, पहले 60 विदेशी कंपनियां थी अभी 4000 से ज्यादा हैं, कांग्रेस हो या भाजपा विदेशी कंपनियों के सामने लाल कालिन बिछाती आई हैं, तो आप क्या करोगे?
- उत्तर-पूर्व व कश्मीर की जनता दशकों से आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रही है, भारत के शासक वर्ग सेना के बल से उनके जन आंदोलन को कुचलते आ रहे हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एफसपा) आदि कानूनों के जरिये जनता के मुलभूत अधिकारों को कुचला जा रहा है, आप आने के बाद क्या करोगे?
- विकास के नाम पर पिछले 68 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा जनता को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हर छटवा नागरिक आदिवासी है, जनता को विस्थपित करने वाली टाटा, बिरला, वेदांता, पोस्को, परमाणु संयतंत्रों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े पूंजीपतियों के लिए देश के खनिज भंडारों को लूटने के लिए खोल देंगे? क्या विनाशकारी परमाणु संयंत्रों को अनुमति देंगे?
- भ्रष्टाचार इस पूंजीवादी व्यवस्था की नसों में बसा हुआ है, विदेशी कंपनियां व बड़े पूंजीपति ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं, छोटे कर्मचारी तो बलि का बकरा बनते हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले कार्पोरेट घरानों पर आप कैसे लगाम कसोगे, क्या छीछला लोकपाल कानून काफी है? जबकि भ्रष्टाचार की जड़ उनकी मुनाफा कमाने की हवस है! भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका ठोस प्रोग्राम क्या है?
- केंद्र सरकार 51 प्रतिशत से भी ज्यादा विदेशी निवेश की छूट खुदरा व्यापार में दे रही है. दिल्ली में तो आपने विदेशी निवेश का विरोध किया है, बाकि देश को क्या आप विदेशी निवेश की खुली छूट देंगे, जैसे कांग्रेस, भाजपा, तरुणमूल कांग्रेस आदि दे रही हैं?
- भारत के शासक वर्ग चाहे कोई पार्टी हो जन आंदोलनों का जवाब लाठी-गोली से दे रही है, चाहे वह आंदोलन शांतिपूर्ण हो या फिर सशस्त्र संघर्ष, क्या आप भी ऐसे ही दमनचक्र चला कर जनआंदोलनो का गला गोंटेंगे?
- साम्राज्यवादियों, विदेशी कंपनियों व बड़े पूंजीपतियों के अनुकूल आर्थिक नीतियां बना कर देश के शासकों ने अर्थ व्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है, क्या आप इसे उबरने के लिए मनमोहन, अटलबिहारी की तरह अमेरीका की तरफ देखेंगे या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ नया उपाय निकालेंगे?
- भाजपा व कांग्रेस ने देश के सेनिकीकरण के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं जबकि देश की जनता भुखमरी का शिकार है, 77 प्रतिशत जनता मात्र 20 रुपये में गुजारा करने पर मजबूर है, इस परिस्थिति में क्या आप भी सेना पर ही ध्यान देंगे या जनता के पक्ष में नीतियां बनाएगे?
- देश के शासकवर्गों ने अपने ही देश की जनता पर युध्द छेड़ रखा है, हमारी पार्टी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर देश के मध्य भाग में साढ़े तीन लाख सशस्त्र बलों को लगाया हुआ है, जनवरी 14 को सीआरपीएफ के डीजीपी ने आपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के तहत एक लाख और सशस्त्र बलों से अभियान की शुरुआत की घोषणा की है. सब जानते हैं यह जनता पर यह युध्द आदिवासी इलाकों में मौजूद खनिज संपदा को विदेशी कंपनियों व बड़े पूंजीपतियों को सौंपने के लिए हो रहा है, पूरी दुनिया इस युध्द का विरोध कर रही है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसी तरह और सेना को भेज कर आदिवासी जनता को विस्थपित करेंगे और जन आंदोलन को कुचलने का सिलसिला जारी रखेंगे?
- आपरेशन ग्रीनहंट के तहत सैकड़ों आदिवासी महिलाओं से सामूहिक दुश्कर्म सशस्त्र बलों द्वारा किये गए हैं, सैकड़ों लोगों को झूठी मुठभेड़ों में मारा गया है, सैकड़ों गांवों को तबाह किया गया है, आप क्या इसकी जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलवाएंगे?

देश के बुध्दिजीवियो अरविंद केजरीवाल के जाल में मत फंसो!
साम्राज्यवाद की चाल को समझो! चुनावों का बहिष्कार करो! जनता का पक्ष चुनो!

ओड़िशा की जनता के लिए बॉक्साइट खनिज बना अभिशाप!

आज की दुनिया में युध्द बिना एल्युमिनियम के नहीं लड़े जा सकते. युध्द का अध्ययन करने वाले बुध्दिजीवि आज के युग को एल्युमिनियम के युग की संज्ञा तक दे रहे हैं. क्योंकि एल्युमिनियम आधुनिक युध्द की मुख्य ताकत बन गया है. जहाज, मिसाईल, बम, तोप, इलेक्ट्रानिक वायार व अन्य उपकरणों में एल्युमिनियम बेहद जरुरी तत्व है. क्योंकि यह धातु हल्की होती है जिसका युध्दक उपकरणों में उपयोग बहुत कारगर होता है.

अमेरीकी सरकार आधिकारीक रुप से मानती है कि आधुनिक युध्द तंत्र में एल्युमिनियम बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसके व्यापक उपयोग के बिना किसी भी लड़ाई या युध्द को सफलता तक नहीं पहुंचाया जा सकता.

भारत में 1989 तक 49 प्रतिशत एल्युमिनियम का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए आरक्षित था. लेकिन 1991 के बाद एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण) नीतियों को लागू कर इस पर से प्रतिबंद हटा लिया गया और विश्व बाजार के लिए, साम्राज्यवादियों के फायद के लिए इसे खोल दिया गया. भारत में प्रति व्यक्ति एल्युमिनियम का उपयोग मात्र 650 ग्राम है जबकि साम्राज्यवादी देशों में प्रति व्यक्ति उपयोग 10 से 12 किलो है प्रति वर्ष है. यानि हमारे देश में एल्युमिनियम का उत्पादन अपनी जरुरतों के लिए नहीं बल्कि साम्राज्यवादी देशों की जरुरत के लिए होता है.

एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है और ओड़िशा में बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं, चाहे नियमगिरी, जगतसिंगपुर हो या फिर गंदमर्धन पहाड़ सब जगह प्रचूर मात्रा में पाया जाता है. ओड़िशा की फासीवादी साम्राज्यवाद प्रस्त नवीन पटनायक सरकार व केंद्र की मनमोहन सरकार विदेशी कंपनियों को इसके ठेके दे रही है. इस कारण से सदियों से निवास करने वाली आदिम जनजातियों, दलितों को अपने घरबार, खेत खलिहानों व जंगलों से उजाड़ा जा रहा है. इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण धातु की मालिक ओड़िशा की जनता के लिए उसकी अपनी संपत्ति ही अभिशाप बन गयी है.

भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन

ओड़िशा के पहाड़ों में जैसे नियमगिरी (रायगढ़ व कालाहांडी जिला) में 30 से 100 फीट मोटी बॉक्साइट की परत है वह भी मात्र जमीन के 3 से 15 फीट नीचे से शुरु होती है. सबसे पहले विस्फोटों के द्वारा पहाड़ को तोड़ कर खनन किया जाता है. उसके बाद उसे शुध्द किया जाता है यानि रिफाईन कर एल्युमिनया बनाया जाता है. वह काम होता है रिफाईनिरियों में. ऐसी ही रिफाईनरी लांजीगढ़ में वेदांता कंपनी ने लगा रखी है. यह नियमगिरी के पास ही है. बॉक्साईट से एल्युमिनिया बनाने के लिए उच्च तापमान की जरुरत होती है. यह ओड़िशा का वातावरण उपल्बध करवाता है. जिस कारण से एल्युमिनियम बनाने की लागत कम हो जाती है. यह इन कंपनियों के लिए मुख्य आकर्षण बना हुआ है.

नियमगिरी से निकलने वाले बॉक्साईट से लांजीगढ़ में वेदांता रिफाईनरी लगाकर एल्युमिया बनाएगा. एल्युमिया बनने के बाद आखरी चरण होता है एल्युमिया से एल्युमिनियम निकालना जिसे स्मेलटिंग यानि पिघलाना कहा जाता है. यह काम लांजीगढ़ रिफाईनरी से एल्युमिनिया लेकर वेदांता की झारसगुडा फैक्ट्री में ले जाकर एल्युमिनियम बनाया जायेगा. इसप्रकार देखा जाये तो एल्युमिनियम बनाने के लिए खदान, रिफाईनरी और पिघलाने वाली फैक्ट्री की जरुरत होती है. इसलिए खदान नियमगिरी में, रिफाइनरी लांजीगढ़ में और पिघलाना झारसागुड़ा में - सब जगह जनता के विनाश की कीमत पर एल्युमिनियम तैयार किया जायेगा. फिर इस एल्युमिनियम से हथियार बनाकर जनता पर ही इस्तेमाल किये जायेंगे! यही है विकास और यही है लोकतंत्र!

सरकारी कंपनी नालको (नेशनल एल्युमिनियम कार्पोरेशन) ओड़िशा में माईनिंग, रिफाइनरी और पिघलाने का कारखाना चलाती है. भारत के 50 प्रतिशत एल्युमिनियम का उत्पादन यही कंपनी करती है. बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडालको छत्तीसगढ़ और झारखंड में एल्युमिनियम का उत्पादन व खनन करती है. हिंडालको की दूसरी रिफाईनरी उत्तकल एल्युमिनियम के नाम से ओड़शा के काशीपुर में बन रही है. इस रिफाईनरी का निर्माण उत्तर ओड़िशा में माईनिंग करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता मालको कंपनी के नाम से तमिलनाडू में माईनिंग, रिफाईनरी व पिघलाने का काम कर रही है. साथ में छत्तीसगढ़ में बालको में भी उसका हिस्सा है और लांजीगढ़ व झारसगुड़ा में नई रिफाईनिरी व पिघलने के कारखाने पर काम जारी है.

एल्युमिनियम उत्पादन व बड़े बांधों के बीच का संबंध

एल्युमिनियम हो या अन्य धातु इनके लिए पानी और बिजली की अबाध आपूर्ति के बिना ये नहीं बन सकतीं. अध्ययन बताते हैं कि 1 टन स्टिल उत्पादन के लिए 40 टन पानी खर्च होता है और 1 टन एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए 1378 टन पानी की जरूरत होती है. और कुल उत्पादन की खर्च का 21 से 30 प्रतिशत पैसा बिजली के लिए खर्च करना पड़ता है. यही कारण है कि पूरी दुनिया में बिजली और पानी के लिए बने बांधों के कारण लाखों लोगों को उजाड़ा जा चुका है. घाना, जमैका, सुरिनाम, ब्राजिल, आईसलेंड, नारवे, मिश्र जैसे देशें में बड़े बांधों के कारण काफी तबाही हुई है.

हिंडालको की रिफाईनरी व पिघलाने वाली भट्टी के लिए रिहंद बांध और इसके पूरक के तौर पर गोविंद बल्भपंत उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में बनाया गया. इस बांध के कारण 2 लाख लोगों को अपनी जमीन व घरबार से हाथ धोना पड़ा. इसमें से ज्यादातर आदिवासी जनता है, जिनको 1961 में उजाड़ने से पहले न तो सुचना दी गयी न ही कोई चेतावनी.

ओड़िशा भारत में बांधों व पिघलाने वाली भट्टियों का हब है. यहां पर हिराकुंड और इंडाल बांध है जब यह बनाया गया तो भारत की एल्युमिनियम कंपनियों को एलकन नामक कनाडा देश की कंपनी ने सब्सीडि दी थी. नालको और कोलाब बांध के निर्माण में 14000 लोगों को विस्थपित किया गया. बालको लोयर सुकतेल बांध बलांगिर में बना रही है. इसके खिलाफ लंबे समय से गंधमर्दान पहाड़ बचाने के लिए आंदोलन जारी है. (जिसकी रिपोर्ट पिछली बार हमने 'जनसंग्राम' में दी थी.)

बड़े बांध पानी के लिए ही नहीं बल्कि एल्युमिनियम कंपनियों को बिजली मुहैया करवाने के लिए भी बनाए जाते हैं. इतना ही नहीं बहुत ही सस्ती दरों पर सरकार द्वारा कंपनियों को बिजली उपल्बध करवाई जाती है. हिंडालको को 25 साल के लिए 1.99 पैसा प्रति युनिट बिजली देने की घोषणा की तब पूरे देश को 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना पड़ता था. हालात अब भी नहीं बदले हैं. इस लिए देशवासियों को स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि बड़े बांधों को केवल और केवल बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए बनाया जाता है न कि सिंचाई के लिए. सिंचाई के लिए बनाने का लालच देकर कंपनियों की जरुरत पूरी की जाती है. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में बना सुंडरु बांध भिलाई स्टिल प्लांट के लिए बनाया गया, गंगरेल बांध से भी दुर्ग, भिलाई में ही पानी की सप्लाई की जाती है.

कंपनियों और स्थानीय जिला प्रशसान के बीच हर तरह की तिकड़म भिड़ा कर जमीनों पर कब्जा व जनतो विस्थापन करने के लिए साठगांठ रहती है. बहुत सारी जगहों की तरह ओड़िशा के गोपालपुर, काशिपुर, लांजीगढ़ में पोस्को, वेदांता आदि का जिला प्रशासन के साथ यानि कलेक्टर और एसपी के साथ गहरा गठजोड़ है. जिला कलेक्टर और एसपी गांव में आकर जनता पर जमीन देने के लिए दबाव बनाते हैं, उनको मुआवजा देने की बात करते हैं, कंपनी नहीं सरकार भूमि का अधिग्रहण कर रही है जैसे बहाने बनाते हैं. इतना ही नहीं जमीन-जंगल के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या तक करवा दी जाती है, जनता पर सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं, उस से भी बात नहीं बने तो झूठे सुधार कार्यक्रमों का सहारा लिया जाता है जैसे बिरला की उत्तकल एल्युमिनियम कंपनी डॉक्टरों, नर्सों को भेज कर स्वास्थ्य सिविर लगाती है, वेदांता ने तो वेदांता विश्वविद्यालय तक खोल दिया है, जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए दान दे रहा है, यह सब हो रहा है कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व के नाम पर.

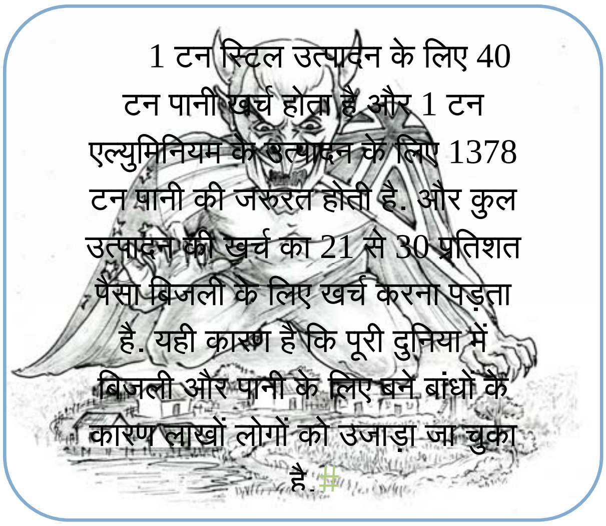

ओड़िशा में बांधों के कारण विस्थापन की जानकारी

परियोजना	गांव विस्थापित	विस्थपित परिवार
हिराकुंड बांध	285	22,144
रिगली बांध	287	11,725
अपर इंद्रावति बांध	99	5,301
बालिमेला बांध	91	2,000
3 सुबरणरेखा बांध	75	5,214
कुल	785	46384

ओड़िशा के काशिपुर में उत्तकल एल्युमिनियम कंपनी का विरोध कर रही जनता पर दिसंबर 2000 में गांव माईकांचा में गोलियां चलाई गयीं उत्तकल कंपनी बिरला की है जिसमें पहले नॉरसक नार्वे देश और इंडल, टाटा और एलकेन कनाडा देश का भी संबंध था. जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन रिफाइनरी के निर्माण के खिलाफ कर रही थी. जहां रिफाईनरी बनाई जा रही थी वहां अधी जमीन का अधिग्रहण भी पूरा नहीं हुआ था. वह गैर कानूनी थी. ऐसा ही गैर कानूनी काम स्टारलाईट-वेदांता ने नियमगिरी में किया. उसे न तो मंजूरी मिली थी न ही अधिग्रहण किया था लेकिन उसने रिफाईनरी का निर्माण कर दिया. वेदांता की रिफाईनरी के लिए नियमगिरी में माईनिंग होना जरुरी है. नहीं तो रिफाईनरी नहीं चलेगी.

नियमगिरी की स्थानीय 'डोंगरिया कोंध' जनता अपने पहाड़ को बचाने के लिए जीवनमरण का संघर्ष छेड़े हुए है. नियमगिरी पहाड़ को 'नियमराजा' वह अपना देवता मानते हैं. उनका आंदोलन विश्वप्रसिध्द हो चुका है. वेदांता का लांजीगढ़ में उत्पादन 50 प्रतिशत घट गया है, उसके मालिक अनिल अग्रवाल कहते हैं कि रोज 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है.

न केवल सरकार और कंपनी आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरजोर कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा खड़े किये गए एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. सेव द चिल्ड्रन ओर सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे संगठन जनता की संघर्ष की चेतना को घुण की तरह खाने का काम करते हैं. उनको संघर्ष से दूर ले जाते हैं.

1997 से लेकर 2005 तक वन व पर्यावरण मंत्रालय ने पेसा कानून को ताक पर रखते हुए 881 माईनिंग परियोजनाओं के लिए 60476 हेक्टयर वन भूमि को देने की मंजूरी दी.

ओड़िशा में बड़ी कंपनियों, खदानों के कारण न केवल पर्यावरण प्रदुषित हो रहा बल्कि सामाजिक रुप से भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं. रिफाईनरियों से निकलने वाली राख, धुआं न केवल हवा को प्रदुषित करते हैं बल्कि फसलों के उत्पादन पर भी बुरा असर डाल रहे हैं. पानी में फलोराईड की मात्रा अधिक हो गयी है. नदियां गंदी हो गयी हैं जिनका न तो जानवर पानी पी सकते न ही इंसान और न ही सिंचाई के काम आ सकती हैं. एल्युमिनियम खदान गहरे जंगलों व पहाड़ों को ध्वस्त कर रही हैं जिसकारण से नदियों के स्रोत खत्म हो रहे हैं. बॉक्साईट माइनिंग व नदियों का गहरा रिश्ता है जिसे पहले भी बताया जा चुका है. गंदमर्धान पहाड़ में दर्जनों झरने हैं जो सुकतेल नदी का निर्माण करते हैं, अगर पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो नदी कहां से बचेगी. एल्युमिनियम की उत्पादन नदियों को सुखा देगा.

रिफाईनरियों से 'भारी धातु' रेडियो एक्टीव तत्व और जहर निकलता है. जिसे 'रेड मड या लाल कीचड़' कहा जाता है. रिफायनिरियां इन को पास की झीलों या जमीन में दफना देती हैं. या फिर समुंद्र में भी दफन करती हैं. यह बड़े पैमाने पर भूमि के नीचे जल को खराब कर देता है.

1997 से लेकर 2005 तक वन व पर्यावरण मंत्रालय ने पेसा कानून को ताक पर रखते हुए 881 माईनिंग परियोजनाओं के लिए 60476 हेक्टयर वन भूमि को देने की मंजूरी दी

यह विकास है, लाखें जनता को विस्थपित कर, हजारों हेक्टयेर जंगल को नष्ट कर, भूमि को बर्बाद कर और पहाड़ों को ध्वस्त कर, नदियों को सुखा कर किया जा रहा है. और इस 'स्थाई विकास' के लिए वेदांता को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से नवाजा गया है.

ओड़िशा में सबसे ज्यादा एमओयू स्टील, पावर और बॉक्साइट क्षेत्र में हुए हैं. कुल मिलाकर दृश्य साफ है, अगर माईनिंग, रिफाईनरी और कारखाने लगेंगे तो वह आदिवासी जनता के विस्थापन, विनाश की कीमत पर लगेंगे. कोई भी राजनीतिक पार्टी सिवाए माओवादी पार्टी के इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि आदिवासी जनता को बचाया जा सकता है. साम्राज्यवाद और पूंजीपतियों के सामने सभी अंततः घुटने टेक देती हैं. माओवादी पार्टी ओड़िशा की जनता से आव्हान करती है कि वह अपने राज्य को इन दानवी कंपनियों के चंगुल से बचाने के लिए माओवाद की राह चुने. नहीं तो भविष्य सामने हैं. पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी जब माईनिंग, रिफाइनरियां जल-जंगल-जमीन को बर्बाद कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे? क्यों हमें पैदा किया जब कुछ खाने व कमाने के लिए नहीं बचा था?

संपादकीय नोट - यह लेख सनहति वेबसाईट पर अमित भोसले द्वारा 'आउट ऑफ अर्थ - इस्ट इंडिया आदिवासी ओर एल्युमिनियम कार्टेल' नामक पुस्तक की समीक्षा पर आधारित है. इस पुस्तक के लेखक हैं फेलिक्स पाडेल और समरेंद्र दास. इस लेख को पूरा पढ़ने के लिए लॉगऑन करें www.sanhati.com

विकास के नाम पर विनाश जारी है! मंजूरी देने वाली सरकारें जनता की हत्यारी हैं!

ओड़िशा विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

कंपनियों को खजाना और जनता को मौत बांटती सरकार

- अरुंधति राय

ओड़िशा में मौजूद बॉक्साइट की कीमत 2270 अरब डॉलर है. यह रकम भारत के सकल घरेलू उत्पाद से दोगुनी है. यह आंकड़े 2004 की कीमत पर आधारित हैं. वर्तमान में उसकी कीमत 4000 अरब डॉलर के करीब होगी. इसमें से आधिकारिक तौर पर सरकार को 7 फीसदी से कम रॉयल्टी मिलेगी. .....

क्या कभी हम यह जान पायेंगे कि इस लूट में किस राजनीतिक दल, मंत्री, सांसद, नेता, जन, एनजीओ, विशेषज्ञ और अधिकारी का प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से कितना हित जुड़ा है?

.....

बीते चुनाव में खर्च हुए दो अरब डॉलर आखिर कहां से आए? चुनावी पैकेज के नाम पर सियासी दलों और नेताओं ने मीडिया को जो अरबों रुपये बांटे हैं, वे कहां से आए? ....

इस तथ्य से हम क्या समझें कि ऑपरेशन ग्रीनहंट के सीईओ और देश के केंद्रीय गृहमंत्री (2011 में) पी. चिदंबरम ने कॉरपोरेट वकील के तौर पर अपने करियर में कई खनन कंपनियों की नुमाइंदगी की है?

इस तथ्य से हम क्या अर्थ निकालें कि चिदंबरम वेदांता के गैर कार्यकारी निदेशक थे और 2004 में उस पद से ठीक उस दिन इस्तीफा दिया जिस दिन उन्हें देश के वित्तमंत्री के तौर पर शपथ ली?

इस सत्य से हम क्या समझें कि वित्तमंत्री बनने के बाद चिदंबरम ने सबसे पहले विदेशी निवेश के जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी उसमें से एक प्रस्ताव मॉरिशस की कंपनी ट्विस्टार होलिडंग्स का था जिसने वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टारलाइट के शेर खरीदे?

यह जान कर भी हम क्या करें कि ओड़िशा के एक कार्यकर्ता ने वेदांता पर सरकारी नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकद्दमा दायर किया और बताया कि कैसे यह कंपनी मानवाधिकारों का हनन और पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है और उसकी करतूतों के कारण नॉर्वेजियन पेशन फंड ने निवेश वापस ले लिया, तो जस्टिस कपाड़िया ने यह सलाह दी कि वेदांता की जगह यह प्रोजेक्ट उसकी सिस्टर कंपनी स्टारलाईट को दे दिया जाये? जस्टिस कपाड़िया ने बेपरवाह अंदाज में भरी अदालत में कहा कि उनके पास भी स्टारलाइट कंपनी के शेयर्स हैं. और उसने स्टारलाइट कंपनी को जंगल में खनन की अनुमति भी दे दी.....

अगर कोई यह सोच रहा है कि राजनांदगांव एयरफोर्स बेस का निर्माण, बिलासपुर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर, गैर कानूनी गतिविधि विरोध कानून, छत्तीसगढ़ स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, (और अब 2013 के आखिर में आपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के तहत 26 जनवरी से 2 फरवरी तक देश में जारी देशव्यापी दमन अभियान - संपादक मंडल) और 'आपरेशन ग्रीनहंट' जंगल से कुछ हजार माओवादियों को बाहर निकालने के लिए हैं तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है. 'आपरेशन ग्रीनहंट' से जुड़ी बहस में मुझे आपातकाल की आहट नजर आती है. (यहां बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कश्मीर की छोटी सी घाटी को कब्जे में रखने के लिए 6 लाख सैनिकों की जरुरत पड़ रही है तो दंडकारण्य के विस्तृत पहाड़ी इलाके और जंगली इलाके में कितने सैनिकों की जरुरत होगी?)

पाठक साथियो - वैसे तो जानीमानी बुध्दिजीवि अरुंधति राय का यह लेख 2009 नवंबर में लिखा गया था. लेख बहुत लंबा है और पुराना भी, लेकिन लिखे विषय का महत्व आज भी बरकरार है जब भारत के शासक वर्गों ने आपरेशन ग्रीनहंट का तीसरा चरण शुरु कर दिया है. संपादक मंडल

'जनसंग्राम' अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, डाउनलोड करने के लिए लॉगऑन करें :-

www.bannedthought.net/jansangram

इसके अलावा डीके एसजेडसी द्वारा प्रकाशित 'प्रभात', शहीदों की जीवनियों सहित पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पुस्तिकाओं, पर्चे, पोस्टरों को भी यहां से डाऊनलोड किया जा सकता है.

पाठकों से अपील

'जनसंग्राम' आपकी पत्रिका है, तमाम पाठक साथियों से अपील है कि पत्रिका के लिए आपके इलाके में जनता पर होने वाले दमन, प्रतिरोध, पीएलजीए के दुश्मनों पर हमलों, लुटेरी सरकारी नीतियों व विस्थापन के खिलाफ, जल-जंगल-जमीन के लिए उठने वाले आंदोलनों पर नियमित रिपोर्टस भेजें. पत्रिका पर अपनी सलाह, सुझाव व आलोचना भेजें!

संपादक मंडल - 'जनसंग्राम'

कार्यशैली

- कामरेड स्तालिन

यह लेख महान शिक्षक कामरेड स्तालिन की पुस्तक 'लेनिनवाद के मूलसिध्दांत' नामक पुस्तक से लिया गया है. हमारी आशा है कि पार्टी कार्यकर्ता इसे ध्यानपूर्वक पढ़ कर इस पर अमल करेंगे और अपनी कमजोर कार्यशैली को छोड़कर लेनिनवादी कार्यशैली को अपनाएंगे जिससे क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ सके. यह लेख पार्टी द्वारा शुरु किये गए बोल्शेविककरण अभियान के तहत छापा जा रहा है.

संपादक मंडल

यहां साहित्यिक कार्यशैली का उल्लेख नहीं कर रहा हूं. मेरा कार्यशैली से मतलब है - काम करने के उस ढंग से जो लेनिनवादी व्यवहार की अपनी विशेषता है और जिससे एक खास तरह का लेनिनवादी कार्यकर्ता उत्पन्न होता है. लेनिनवाद सिध्दांत और व्यवहार का स्कूल है जिसमें पार्टी और राज्य के एक विशेष तरह के कार्यकर्ता तैयार होते हैं. जिनकी एक विशेष तरह की कार्यशैली यानि लेनिनवादी शैली होती है. इस शैली के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? इसकी विशेषताएं क्या हैं?

इसके दो लक्षण हैं -

1. रुसी क्रांतिकारी उत्साह
2. अमेरिकी कार्यकुशलता

पार्टी और राज्य के कार्य में इन दोनों लक्षणों के जोड़ से बनी शैली लेनिनवादी शैली कहलाती है. अकर्मण्यता, जड़ता, अन-उदारता और मानसिक गतिशून्यता के विरुध्द और पूरानी परंपराओं की गुलामी के विरुध्द रुसी क्रांतिकारी उत्साह रामबाण के समान है. वह एक जीवन देने वाली शक्ति है जो विचार को उत्तेजित करती है. कार्य को गति देती है और पुराने बंधनों को तोड़कर आगे का रास्ता खोलती है. उसके बिना कोई प्रगति संभव नहीं है.

अगर उसका संबंध अमेरिकी कार्यकुशलता के साथ न जोड़ा जाये तो रुसी क्रांतिकारी उत्साह भी व्यवहार में विकृत होकर खोखले ''क्रांतिकारी'' मानिलोववाद का (मतलब मिथ्या आत्मसंतोष) का रुप धारण कर सकता है. इस विकृती के दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं. कुछ लोगों का विश्वास है कि फरमानों (प्रस्ताव या आदेशों सं.) द्वारा हर चीज की व्यवस्था हो सकती है. हर तरह का सुधार किया जा सकता है.इस तरह के विश्वास वाले लोग जिस तरह हर बात के लिए चटपट 'क्रांतिकारी' हल निकाल लेते हैं और 'क्रांतिकारी' योजनाओं के अंडे दिया करते हैं, उसे कौन नहीं जानता? एक रुसी लेखक इलिया एहरेनुबर्ग ने अपनी कहानी द पर्कोमान (मतलब पक्का कम्युनिस्ट मानव) में इस तरह के एक 'बोल्शेविक' का चित्रण किया है. उस 'बोल्शेविक' ने एक पूर्णतः आदर्श व्यक्ति की रचना का सूत्र खोज निकालने का निश्चय किया... और इस 'कार्य' में खो गया. इस कहानी में कुछ अतिश्योक्ति (बढ़ाचढ़ा कर पेश करना सं.) है, तो भी वह उपरोक्त बीमारी का एक सही चित्र प्रस्तुत करती है. लेकिन मैं समझता हूं कि इस रोग का उपहास जिस निर्ममता से लेनिन ने किया है वैसा और किसी ने नहीं किया है. इस चीज की चटपट योजना बना लेने और फतवों (आदेशों सं.) द्वारा हर काम की व्यवस्था कर लेने की इस धारणा को लेनिन ने 'कम्युनिस्ट घमंड' कहा है.

लेनिन ने लिखा है, ''कम्युनिस्ट घमंड एक ऐसे आदमी का लक्षण है जो समझता है कि वह केवल आदेश निकाल कर सब प्रश्नों को हल कर सकता है.'' (लेनिन, नई आर्थिक नीति और राजनीतिक शिक्षा विभाग के कार्यभार, ग्रंथावली, खंड 9, पृ. 273)

लेनिन अक्सर सीधे दैनिक काम और खोखले 'क्रांतिकारी' शब्दाडंबर का भेद बताया करते थे. वह बराबर इस काम पर जोर देते थे कि यह तथाकथित 'क्रांतिकारी' योजनाबाजी लेनिनवाद के सिध्दांतों और भावना के सर्वथा विरुध्द है.

उन्होंने लिखा है, ''...लच्छेदार भाषा का प्रयोग कम करके अपने दैनिक कार्य की मात्रा बढ़ाओ.''

''...राजनीतिक आतिशबाजी का प्रदर्शन कम करो, कम्युनिस्ट निर्माण के साधारण लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर अधिक ध्यान दो.'' (लेनिन, एक महान शुरुआत, ग्रंथावली, खंड 9, पृ. 230-440)

अमेरिकी कार्यकुशलता ''क्रांतिकारी'' मानिलोववाद और हास्यास्पद योजनाबाजी की शत्रु है. यह कार्यकुशलता वह अजेय शक्ति है जो न बाधाओं को जानती है और न उन्हें स्वीकार करती है. अपने उद्यम और अध्यवसाय के बल से कार्यकुशल व्यक्ति सभी बाधाओं को दूर कर देता है और जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे करता जाता है, चाहे वह काम कितना ही छोटा क्यों न हो. इस प्रकार की

कार्यकुशलता (अमेरिकी निपूणता) के बिना कोई भी रचनात्मक कार्य पूरा नहीं किया जा सकता.

लेकिन उसका (अमेरिकी निपूणता) जोड़ रुसी क्रांतिकारी उत्साह के साथ न हो तो अमेरिकी कार्यकुशलता के विकृत होकर संकुचित और सिध्दांतहीन व्यावसायिकता के कारण कभी-कभी कुछ 'बोल्शेविकों' ने क्रांतिकारी कार्य को त्याग दिया है उनके इस रोग की बात किसने नहीं सुनी है? बी. पिलनियाक की बजंर वर्ष नाम कहानी में हमें इस विचित्र रोग का परिचय मिलता है. उसमें कुछ ऐसे 'बोल्शेविकों' का चित्रण किया गया है जिनकी इच्छाशक्ति और व्यावहारिक संकल्प काफी दृढ़ हैं और जो काफी 'जोरशोर' से 'काम' करते हैं. लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाते, वे यह नहीं जानते कि वे 'क्या कर रहे हैं'' और इस कारण क्रांतिकारी पथ से भटक जाते हैं. इस संकुचित व्यावसायिकता का उपहास करने में लेनिन से अधिक निर्ममता और किसी ने नहीं दिखाई. उन्होंने इसे ''कूपमंडूक व्यावहारिकता'' और ''नामसझ बनियापन'' बतलाया है. लेनिन ने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्य करने की और दैनिक कार्यक्रम के संबंध में क्रांतिकारी संबंध बनाए रखने की आवश्यकता में और इस संकुचित दृष्टिकोध में भेद बतलाया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सिध्दांतहीन व्यावसायिकता लेनिनवाद के सिध्दांत के उतना ही विरुध्द है जितना कि तथाकथित 'क्रांतिकारी' योजनावाद.

पार्टी और राज्य के कार्यक्षेत्र में रुसी क्रांतिकारी उत्साह और अमेरिकी कार्यकुशलता के इस सम्मिश्रण का नाम है लेनिनवाद.

इन्हीं दो गुणों के जोड़ से निपुण लेनिनवादी कार्यकर्ता पैदा होते हैं और लेनिनवादी कार्यशैली का निर्माण होता है.

पेज नंबर 25 का शेष

लोयर सुकतेल बांध के निर्माण के विरोध में, नशा मुक्ति अभियान पर, पुलिस भर्ति का विरोध करते हुए हजारों प्रर्चों व पोस्टरों की छपाई की गयी. इसके अलावा हस्तलिख पोस्टर भी कई मुद्दों पर एरिया में लगाए गए - काटाबाजी सफाई, लोयर इंद्रा (टिकाली बांध) के विरोध में, कोम्मेमुंडा ग्रामपंचायत सरपंच के ऊपर हमले के विरोध में, जामपाडा पुलिस भर्ति के विरोध में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के विरोध में, लाटूर में दलितों के शोषण के विरुध, कंचाल मुठभेड़ के खिलाफ, दारु भट्टियों, दुकानों को बंद करवाने के लिए चेतावनी पोस्टर लगाए गए.

साल की दूसरी तिमाही में भी प्रचार जोरो पर चलाया गया. एरिया में मजदूर दिवस, ग्रीनहंट, तेंदुपत्ता रेट आदि पर पर्चे छापे गए. इसके अलावा कई विषयों पर हस्तलिखत पोस्ट डाले गए. महखंड में 4 जन पुलिस में भर्ति हुए उनको चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए, मुखबिर डिगोर खान, जन्मेपज्यो बाग, पुलिस कैंप के विरोध में पोस्टर लगाए. कोदलीपल्ली जमीन समस्या पर, जंगल बचाने के लिए पोस्टर डाले गए. कोंदाई ग्राम पंचायत में कुली मजदूरों की समस्या पर पोस्टर डाले.

किसानों को महंगे बीच किटनाशकों से घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. महंगाई के विरोध में किसानों को संगठित होकर संघर्ष करने का आव्हान देते हुए पोस्टर व पर्चे वितरित किये गए. हिंदी व ओड़िया भाषा में सैकड़ों की संख्या में पर्चे-पोस्टर छापे गए. बस्तरीय जनता के जानी दुश्मन महेंद्र कर्मा का पीएलजीए द्वारा सफाया गया. इस पर भी ओड़िया व हिंदी में पर्चे छापे गए.

पीएलजीए डॉक्टरों ने जनता का किया इलाज

हर साल जुलाई महीने में गांव-गांव में बीमारियों की बाढ़ सी आ जाती है. एक तरफ सरकार विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में न तो हस्पताल है न ही दवाई. अगर हस्पताल हैं भी तो नाम मात्र, वहां से डॉक्टर हमेशा नदराद रहते हैं.

पीएलजीए ने इस परिस्थिति को देखते हुए खुद इलाज करने का बिड़ा उठाया. अपने सीमित साधनों के साथ, दमन के कारण कम होती जा रही दवाइयों की स्पलाई के बावजूद जनता का इलाज किया. एरिया के तीन गांव बुरी तरह से बीमारियों से पीड़ित थे. उन गांव के 200 लोगों का इलाज पीएलजीए के डॉक्टरों ने किया. इनमें से दो जन तो बहुत गंभीर रुप से बीमार हुए थे, एक जन को टीवी थी तो दूसरा एक मजदूर था जो बहार काम के दौरान घायल हुआ था. उसके मालिक ने उसे राम भरोसे छोड़ दिया था. अब दोनों की हालत सुधर गयी है. इस से पता चलता है कि न तो सामंती जमींदार, मालिक और न ही सरकार जनता के विकास की तरफ ध्यान दे रही है. उनका सारा ध्यान जनता की जमीन हड़पने और रोड़ आदि बनाने पर लगा हुआ है.

भगत सिंग की बात सुनो - माओवाद की राह चुनो

भगत सिंग के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की श्रृंखला

विद्यार्थी और राजनीति

पाठक दोस्तो! अमर शहीद भगत सिंह-राजगुरु-सुखदेव का शहादत दिवस 23 मार्च आ रहा है. शहीद भगत सिंग व उसके साथी केवल बंदूक उठा कर अंग्रेजों को भगाने की शपथ खाने वाले और हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाने वाले युवक भर नहीं थे. उनकी विचारधारा और राजनीति को भारत के शोषक-शासक वर्ग हमेशा से छुपाते हुए आए हैं. उनको सिर्फ एक सिरफिरे आतंकवादी की तरह पेश किया जाता है. आज तक संसद भवन में उनकी फोटो तक नहीं लगाई गयी. शहीद भगत सिंग केवल अंग्रेज भाग जाएं इसकी के लिए फांसी नहीं चढ़े थे, बल्कि उनके क्रांति के प्रति स्पष्ट विचार थे. उनका मानना था था कि हमारा मकसद केवल यह नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर बैठ जाएं, हमारा मकसद है मजदूर किसान वर्ग की राजसत्ता का निर्माण करना, इस देश की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाना. जब तक आदमी द्वारा आदमी का शोषण जारी रहेगा, हमारा संग्राम जारी रहेगा. यह थे उनके सपने. आज भी शहीद भगत सिंग व उसके साथियों के सपने अधूरे हैं, माओवादी पार्टी उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्षरत है. शहीद भगत सिंग शानदार व परिपक्व विचारक थे. हम उनकी शहादत दिवस के अवसर पर उनके लिखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रकाशित करने का सिलसिला शुरु कर रहे हैं. जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे. आशा है पाठक साथी हमें अपनी अमूलय राय से परिचीत करवाएंगे.

इस महत्वपूर्ण राजनीति मसले पर यह लेख जुलाई 1928 में पंजाब से छपने वाली क्रांतिकारी पत्रिका 'किरती' में छपा था। उन दिनों विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा न लेने की सलाहें देते थे, जिनके जवाब में यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख सम्पादकीय विचारों में छपा था। - संपादक मंडल

इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान (विद्यार्थी) राजनीतिक या पोलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है । विद्यार्थी से कालेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं कि वे पोलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोंगो की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा-मंत्री है, स्कूलों-कालेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ानेवाला पालिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टुडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से वद्यार्थी -सप्ताह मनाया जा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचन्द्र नन्दा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पोलिटिक्स में हिस्सा नही लेना चाहिए।

पंजाब को राजनितिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ (politically backward) कहा जाता है इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम किये है? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली है? फिर क्या कारण है किह हम इस मैदान में सबसे पीछे है? इसका कारण स्पष्ट है कि कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजुल होती है, और विद्यार्थी – युवा-जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हे इस सम्बन्धमें कोई भी ज्ञान नहीं होता. जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिव वे ऐसी कच्ची-कच्ची बाते करते हैं किसुनकर स्वंय ही अफसोस कर बैइ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता. जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है. इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए. यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान

> **यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाये.**

उस ओर लगा देना चाहिए लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाये. ऐसी शिक्षा की कोई जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि ''काका तुम पोलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो. तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे.''

बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है. इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक 'नौजवानों के नाम अपील, प्रिंस क्रोपोटकिन' पढ़ रहा था.एक प्रोफसर साहब कहने लगे, यह कौन-सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा-प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिध्द है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था. प्रोफेसर की 'योग्यता' पर लड़का हंस भी पड़ा. और उसने फिर कहा - ये रुसी सज्जन थे. बस! 'रुसी!' कहर टूट पड़ा! प्रोफेसर ने कहा कि 'तुम बोल्शेविक हो, क्योंकि तुम पोलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो.''

देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता! अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं?

दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु और सुभाषचंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वाइसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वो पालिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों को प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पोलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जायेगी, तो फिर यह भी पोलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जायेगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज? फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ. क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं तब तक वफादारी करने वाला वफादार नहीं बल्कि गद्दार है, इंसान नहीं पशु है, पेट के गुलाम हैं. तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें.

सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरुरत है, जो तन-मन-धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दें. लेकिन क्या बुड्ढों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों और जंजालों में न पड़े हों, विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं, यदि उन्हेंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो और सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परिक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो.

सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरुरत है, जो तन-मन-धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दें. लेकिन क्या बुड्ढों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों और जंजालों में पड़ने से विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं, यदि उन्हेंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो और सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परिक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो.

क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कालेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पोलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहां थे जो उनसे कहते - जाओ, जाकर शिक्षा हासिल करो. आज नेशनल कालेज, अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह के बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जायेंगे? देखते हैं उनकी तुलना में पंजाब का विश्वविद्यालय कितने योग्य आदमी पैदा करता है? सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं. क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग-अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पायेंगे? नवजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किये गए अत्याचार भूल नहीं सकते. वे यह भी समझते हैं कि उन्हें क्रांति की जरुरत है. वे पढ़ें, जरूर पढ़ें! साथ ही पोलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें. अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें. वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता.

पहली बार प्रकाशित 'किरती' जुलाई 1928
लेखक - भगत सिंह

दुश्मन की मांद : जेलों में जनयुद्ध का परचम लहरा रहे तमाम कामरेडों को 'जनसंग्राम' का लाल सलाम

भारतीय जेलों में राजनीतिक बंदियों के गूंजते नारे

दिसंबर 2013 को भारतीय जेलों में बंद 6

राजनीतिक बंदियों के आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का आव्हान किया गया था. जिसके प्रचार का असर 25 जनवरी से पहले ही जेल के बंदियों पर दिखने लगा. अलग-अलग जेलों में बंद कामरेडों ने जेल की अमानवीय यातनाओं व हालातों के खिलाफ भूखहड़तालों का सिलसिला जारी कार दिया. 26 जनवरी के बाद से अब भी जारी है. दुश्मन के सामने दृढ़तापूर्वक जनयुध्द का परचम लहरा रहे तमाम कामरेडों, प्यारे नेताओं को 'जनसंग्राम' लाल सलाम पेश करती है और आव्हान करती है कि फासीवादी राज्य के खिलाफ उसकी मांद में ही शहीदों को याद करते हुए संग्राम जारी रखें. हम जनता से व राजनीतिक कैदियों के परिजनों से, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि उनकी बिना शर्त रिहाई व जेलों में मानवीय हालातों को बनावाने के लिए संघर्ष को तेज करें.

17 जनवरी को झारखंड के हजारीबाग जिला की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल में 200 महिला-पुरुषों ने अपनी मांगों को लेकर भूखहड़ताल का आयोजन किया. उनकी मांग थी कि उन 31 कैदियों को रिहा किया जाये जो बरसों पहले अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा जानबूझ कर उनको वहां रखा जा रहा है. इससे पहले भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड नारायण सान्याल, रवि शर्मा और नारायण रेड्डी के नेतृत्व में 1300 कैदियों ने जेल में आंदोलन किया था. जेल के अंदर उन्होंने धरना दिया जिसमें तमाम कैदियों ने भाग लिया और जेल प्रशासन के खिलाफ जेल कें अदंर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वह फिर 30 जनवरी से भूखहड़ताल पर चले जायंगे.

लेकिन फासीवादी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया इस कारण से मजबूरन फिर हमारे कामरेडों को 30 जनवरी से भूखहड़ताल पर जाना पड़ा. यह समाचार लिखे जाने तक उनकी भूखहड़ताल को पांचवा दिन पहुंच चुका था. करीब 100 कैदी लगातार भुखहड़ताल कर रहे हैं.

जेल प्रशासन के अनुसार महाराष्ट्र की नागपुर जेल में 169 कैदियों ने 30 जनवरी भूखहड़ताल शुरु कर दी है. हालांकि मानवाधिकार वकीलों का कहना है कि हर रोज 200 कैदी भूखहड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं. और हर रोज यह हड़ताल जारी है.

इधर हमारे राज्य ओड़िशा बहरमपुर सरकिल जेल के कैदियों ने भी 30 जनवरी को भूखहड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया. उनकी मांग है कि कैदियों सीधे कोर्ट में पेश किया जाये और उनकी सुनवाई नियमित की जाये. कैदियों को विडियों कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल किया जाता है, जहां वह अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते न ही अपने उपर लगे आरोपों पर बहस कर पाते.

भारतीय जेलों में 3 लाख ऐसे कैदी हैं जिनको सजा नहीं सुनाई गयी हैं और जेलों में सड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं है, या उनके परिजनों की हालत बहुत गरीब है जो महंगी कोर्ट कार्रवाइयों में भाग नहीं ले पाते. और खास बात यह है कि यह सब कैदी गरीब वर्ग से संबंध रखते हैं. झारखंड की जेलों में 135 ऐसे लोग हैं जो अपनी 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन सरकार उनको अभी भी रिहा नहीं कर रही.

वहीं सितंबर में झूठे केस में अरेस्ट किये गए राजनीतिक कैदी प्रशांत राही ने भी जेल से एक पत्र लिख कर अपने उपर हुई यातनाओं को उजागर किया है और बुध्दिजीवियों से अपील की है कि काले कानून यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाई जाये जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को फासया गया है. यूपीए ऐसा काला कानून है जिसमें शक के आधार पर, या माओवादियों को मदद करने के आरोप लगकर जेलों में ठूसा जाता है. इस के अंदर जमानत का भी प्रावधान नहीं है. यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, रौल्टएक्ट की नकल है जो उनकी संतान काले अंग्रेजों द्वारा जारी है.

महाराष्ट्र जेल में जेल बंदियों की तरफ से एक पत्र मिडिया को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नागपुर जेल में 7 महिलाओं सहित 177 कैदी है जिन पर माओवादी समर्थक होने का या माओवादी होने का आरोप लगाकर यूपीए, मकोका व मर्डर केश लगाकार गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने लिखा है कि हम बिना सजा पाये ही जेल काट रहे हैं.

उनहेंने जनता, बुध्दिजीवियों, जनवादी अधिकार समुहों, कानूनी कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आपकी सक्रिय मदद व संघर्ष के बिना हमारा संघर्ष अधूरा है. आपसे अपील है. उनका आव्हान है कि आप सब हमारे संघर्ष का समर्थन करें.

'जनता पर युध्द' आपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण की शुरुआत

40 हजार सशस्त्र बलों के नेतृत्व में चलाया गया जनता पर युध्द, माओवादी पार्टी के उन्मुलन का था लक्ष्य!

आपरेशन ग्रीनहंट की शुरुआत 2009 के मध्य में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर की थी. केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के अंदर से माओवादी उन्मुलन के लिए विशेष बटालियनों का गठन किया गया था जिनका नाम था कंबैट बटालियन फॉर रिजयूल्ट एक्शन यानि कोब्रा. अगस्त 2009 में आपरेशन ग्रीनहंट का पहला शिकार बीजापुर-दांतेवाड़ा जिला की जनता बनी थी. जब कोब्रा ने पहला हमला हमारी पार्टी के एक तकनीकि कैंप पर सिंगनमडगू गांव पर किया था तो पीएलजीए ने जबरदस्त जवाब दिया था और कोब्रा के 6 जवानों को मार गिरा दिया था और कई जन को घायल किया था. उसके बाद कोब्रा, सीआरपीएफ, एसपीओ, जिला पुलिस के साथ जनता पर पाशविक दमन चलाया गया. दर्जनों महिलाओं से सामूहिक बलात्कार किये गए और कई गांवों को जला डाला गया. लेकिन पीएलजीए के बढ़ते हमलों के बाद सरकार ने ब्रिगेड स्तर के दमन अभियान शुरु किये. 2011 में आपरेशन विजय, हाका जैसे चलाकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गयी, सेना की मदद ली जाने लगी, कोंडागांव, नारायणपुर जिलों में प्रशिक्षण के नाम पर सेना के कैंप भी बिठा दिये गए लेकिन सारी कोशिशें बेकार हुई.

भारतीय राज्य बेशर्मी के साथ फासीवादी रुप दिखा रहा है. कहने को तो कानून व व्यवस्था का मसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ग्रीनहंट की शुरुआत के साथ राज्यों में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती बढ़ा कर केंद्र सरकार धीरे-धीरे अपने हाथों में राज्य सरकार की शक्तियों को छीनता जा रही है. पहले राज्य के पुलिस बल मुख्य रुप से अभियानों का नेतृत्व करते थे, लेकिन एक साजिश के तहत चिदंबरम ने सीआरपीएफ को पिछले दरवाजे से नेतृत्व की भूमिका में लाना शुरु किया और अब सुशीलकुमार सिंदे के मार्गदर्शन में बाकायदा घोषणा कर सीधा सीआरपीएफ के नेतृत्व में सीआरपीएफ, केंद्र सरकार के अन्य अर्ध सैनिक बल हमलों की अगवाई कर रहे हैं. वे अपने ही संविधान के खिलाफ जाकर ऐसे निर्णय कर रहे हैं.

इस प्रकार अब सरकार ने ग्रीनहंट के तीसरे चरण की शुरुआत की है. 26 दिसंबर 2013 को 40 सीआरपीएफ जवानों के नेतृत्व में एक देशव्यापी हमले की शुरुआत की. एक साथ 8 माओवाद प्रभावित राज्यों में हमला कर माओवादी पार्टी को जड़ से खत्म करने के इरादे से यह अभियान चलाया गया. इस अभियान में बड़े पैमाने पर बीएसएफ, आईटीबीपी, जिला फोर्स, कोब्रा, महाराष्ट्र. में सी-60, ओड़िशा में एसओजी, छत्तीसगढ़ में कोया कमांडो, आंध्रप्रदेश के ग्रेहाउंड्स, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (सीएएफ), झारखंड में झारखंड जुगुआर जैसे विशेष बलों ने हिस्सा लिया. इतना ही नहीं नेतृत्व में सेना की भी प्रत्यक्ष भागीदारी इस अभियान में रही, दर्जनों एमआई-17 सेनिक हेलिकाप्टर, ड्रोन आदि विमानों का भी प्रयोग किया गया. कहने को तो यह अभियान 26 से 30 दिसंबर तक ही था लेकिन इस समय के 2 दिन बाद तक भी फोर्स जंगलों में खाक छानती रही. यह पहला मौका है जब हमारी पार्टी के खिलाफ सीआरपीएफ के नेतृत्व में इतना बड़ा अभियान चलाया गया. इस अभियान में 10000 हजार केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों सहित राज्यों के 30 हजार विशेष बलों व पुलिस बलों ने भाग लिया. सीआरपीएफ के डीजीपी दिलीप त्रिवेदी ने युध्द की घोषणा करते हुए कहा कि एक साथ सभी राज्यों में अभियान चलाने से माओवादी दूसरे राज्यों में नहीं भाग पायेंगे. इस अभियान की योजना राज्य पुलिस मुखियाओं की पिछली बैठक में बनाई गयी थी. इस अभियान का संचालन राज्य पुलिस के हेडक्वाटरों से समन्वय करते हुए दिल्ली में बैठ कर सीआरपीएफ डीजीपी दिलीप त्रिवेदी कर रहे थे.

एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने मिडीया को बताया कि इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा माओवादी नेताओं का व उनके आधारभुत डांचों का खात्मा किया जायेगा. अभियान की शुरुआत से अंत तक सेना व बीएसएफ के हेलिकाप्टर और यूएवी इसमें मदद करेंगे.

माओ ज्यांती के दिन यानि 26 दिसंबर से शुरु किया गया यह अभियान ओड़िशा में 2 जनवरी तक चलता रहा. बलांगिर-बरगढ़-महासमुंद (बीबीएम) और नुआपाड़ा डिवीजन में उच्चस्तरीय अधिकारियों के प्रत्यक्ष नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन, कुंबिंग अभियान सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया. जगह-जगह घात लगाकर उनके द्वारा पीएलजीए बलों पर हमले करने की कोशिशें की गयीं. जंगल, नदी-नालों, पहाड़ों सब जगह पुलिस बलों का केंद्रीकरण था. कंपनी की संख्या में अलग-अलग ग्रुप इलाके को घेरे हुए थे. नुआपाड़ा डिवीजन के धर्मबांद इलाका में जंगल विभाग के विश्राम घर को कैंप में बदल दिया गया. 300 की संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात कर पूरे एलओएस इलाका में सर्चिंग अभियान चलाया गया. धर्मबांद एलओएस का निर्मूलन करने के लिए कई तरह की साजिश सशस्त्र बलों ने रची, लेकिन जनता की मदद से हमारे दस्ते सुरक्षित रहे. पतोरा और गोदास कैंप के साथ छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ बलों ने समन्वय करते हुए कनपाड़ एरिया में दमन अभियान चलाया.

सोनाबेड़ा एरिया में 25 दिसंबर रात को ही फोर्स ने आना शुरु कर दिया था. बाटी बहाल से छेरी चुव्वा की ओर से, कोलिबीतर की ओर व आलपापली में फोर्स ने डेरा डाला. जामगांव के पास कैंप डाल कर दुश्मन कंपनी-कंपनी की संख्या में कुंबिंग अभियान चलाया. सोनाबेड़ा, जुनापानी, गातिबेड़ा में जनता के विरोध के बावजूद उस पर दबाव डाल कर पुलिस कैंप डालने की भी योजना बनायी. हमारे पूराने सभी डेरा डालने के स्थलों की छानबिन किया. 31 दिसंबर को गांव कडांग पर हमला किया और जनता पर दबाव डाला कि माओवादी दस्तों को पकड़वा दो. जब जनता ने कुछ जवाब नहीं दिया तो 11 ग्रामीणों की बेदम पिटाई सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा की गयी. इसके अलावा दातुनामा व डेकुपानी गांव के किसानों पर भी सशस्त्र बलों ने हमला किया. डेकुनपानी गांव के किसान जब इस हमले के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जिला हेडक्वार्टर में जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक कर माफी मांगी और फिर से ऐसा नही करने का आश्वासन दिया. वहीं 1 जनवरी को जब अपने आतंकी गुंडे सरकारी सशस्त्र बलों को एसपी उमाशंकर दास नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कडंग गांव आया तो जनता ने अपनी समस्या रखी और पिटाई का प्रकरण बताया. लेकिन बेशर्मी के साथ एसपी ने जनता की बातों को नकार दिया.

जनता को आतंकित करने के लिए उनके फोटो उतारे जा रहे हैं, नीजता के अधिकार की धज्जियां सशस्त्र आतंकि बलों द्वारा उड़ाई जा रही हैं. 28 दिसंबर को गांव बहादुरपानी में जनता के फोटो उनके विरोध के बावजूद उतारे गए.

मैनपुर डिवीजन, नियमगिरी, सोहेला, बोडेन, बटांग, गंदमर्धन आदि अन्य इलाकों में भी सरकारी सशस्त्र बलों ने जनता को आतंकित किया.

40 हजार सीआरपीएफ बलों का यह अभियान पूरे देश में विफल हुआ है. कहीं भी माओवादी पार्टी को पुलिस बल नुकसान नहीं पहुंचा पाये निर्मूलन की तो बात दूसरी रही. जनता की मदद से न केवल पीएलजीए बल अपनी रक्षा करने में सफल रहे बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड में हमारे बलों ने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और उसका मनोबल तोड़ा. बिजापुर के मितुल गांव में सीआरपीएफ के उपर दो हमले किये गए जिसमें एक जवान मारा गया और दो घायल हुए वहीं पीएलजीए ने दो इंसास राइफलों पर भी कब्जा करने में सफलता प्राप्त की. इसलिए सीआरपीएफ के डीजीपी ने फिर 14 जनवरी को एक लाख सशस्त्र बलों ने एक नए अभियान की शुरुआत करने की घोषणा करनी पड़ी है

मलकानगिरी में सशस्त्र बलों के ऑलआउट दमन अभियान की निंदा करो!

ओड़िशा डीजीपी प्रकाश मिश्र, मुख्य सचिव जुगल किशोर महापात्र व एसपी अखिलेश्वर सिंग की साजिश कभी सफल नहीं हो पायेगी!!

आंध्रप्रदेश व छत्तीसगढ़ से सटे मलकानगिरी-कोरापुट जिलों में 4 फरवरी 2014 को ओड़िशा के फासीवादी हत्यारे डीजीपी प्रकाश मिश्र ने माओवादियों को खत्म करने के लिए आपरेशन ऑल आउट की घोषणा की. ओड़िशा के मुख्य सचिव जुगल किशोर महापात्र और डीजीपी प्रकाश मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि मलकनगिरी के बालिमेला जलाश्य के पार 6 ग्राम पंचायत एरिया में 'फाइनल अस्ल्ट' चलाया जायेगा. माओवादियों को चारों तरफ से घोराबंदी की जायेगी ताकि न तो माओवादी बाहर जा सकें और न ही दूसरे राज्यों से माओवादी अंदर आ सकें. इस की घोषणा बालिमेला के दौरे के बाद इन बर्बर अधिकारियों ने की है.

डीजीपी ने 24 जनवरी को जिला के सीर्स अधिकारियों के साथ इस इलाके का दौरा किया था. जिस टीम में जिला एसपी अखिलेश्वर सिंग भी थे. यह वही एसपी है जिसने आदिवासी जनता के 13 सपूतों को झूठी मुठभेड़ में मार डाला था.

इस दमन अभियान में सैकडों बीएसएफ जवानों के साथ जिला वलयंटरी फोर्स, एसओजी को उतारा गया है. घमंड से भरे डीजीपी प्रकाश मिश्र बौखालाए कुत्ते की तरह बयान देने के लिए मशहूर है. सितंबर 2013 में 13 आदिवासियों को झूठी मुठभेड़ में मार कर उन्होंने बयान में माओवादियों को इस इलाकें में घुसने की चेतावनी दी थी. लेकिन तमाम दमन के व जनता पर दहशत के बावजूद माओवादी पार्टी को जनता का भरपुर समर्थन मिला और बर्बर डीजीपी के इरादों पर पानी फिर गया था. पीएलजीए कामरेड जनता की मदद से न केवल सुरक्षित रहे बल्कि जनता को संगठित करते रहे. आपरेशन आल ऑउट का भी यही हाल होगा. क्योंकि माओवादी पार्टी कोई आतंकवादी पार्टी नहीं बल्कि जनता की अपनी पार्टी है.

भारत का संविधान सुरक्षा बलों को केवल आत्मरक्षा में ही गोली चलाने की इजाज देता है. लेकिन डीजीपी प्रकाश मिश्र जो भाषा बोल रहा है वह संविधान का उल्लंघन करती है. क्योंकि पुलिस, अर्ध सैनिक बल वहां पर दमन अभियान चला रहे हैं तो निर्दोष जनता पर गोलियां बरसाएंगे, पीएलजीए के उपर हमले करेंगे और बाद में कहानियां लिखेंगे कि माओवादियों ने हमला किया पुलिसबलों ने जवाबी कार्रवाई की और इतने माओवादी मारे गए. यह कहानी हमेशा झूठी होती है. क्योंकि पुलिस के अधिकारी केवल और केवल जनता के दमन के इरादे से, माओवादी पार्टी को खत्म करने के इरादे से ही जंगलों में घुसते हैं. आइये विदेशी कंपनियों व दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों के फायदे के लिए जनता पर किये जाने वाले इस दमन अभियान की निंदा करें और उसे हरा दें.

डिवीजनों से रिपोर्ट

बलांगिर एरिया

छुआछूत का विरोध करो!

बलांगिर एरिया में दशकों से जातिय भेदभाव और छुआछूत की समस्या से दलित और आदिवासी जनता पीड़ित है. निची जाति या छोटी जाति के नाम पर आदिवासी व दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है. उनके ऊपर प्रतिबंद लगाना और गांव से बहिष्कार करना आदि जारी है. यह सब सामंती मुखियाओं की देखरेख में जारी है. हमारी पार्टी आने के बाद जाति विरोधी संघर्ष अपने हाथ में ले रही है और जनता को समझ-बुझा कर ऐसे निर्णयों का विरोध करते हुए एकजुट होकर असली दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित कर रही है.

कुहबहली गांव में भोई (कोंद) जाति और दलित जाति के लोगों का बहिष्कार करने, उनको गांव से निकालने का विचार सामंती मुखिया कर रहे थे. लेकिन पार्टी ने मार्च 2013 में समस्त गांव की आमसभा बुलाकर इसका समाधान किया और आदिवासी व दलितों का सामाजिक बहिष्कार रुकवाया.

गांव नंदुल में भी दलित जाति के लोगों का सामाजिक रुप से बहिष्कार किया हुआ था. गांव की छोटी-छोटी दुकानों से भी उनको सामान खरीदने नहीं दिया जाता था. जुलाई महीने में इस गांव में आमसभा कर इस समस्या का समाधान किया गया.

धर्मशाला के नाम पर पुलिस कैंप का भवन - जनता ने किया ध्वस्त

तुरेकेला ब्लॉक सहित जिले के अन्य ब्लॉकों में सरकार व पुलिस प्रशासन मिलकर पुलिस कैंप के लिए भवनों का निर्माण कर रहा है. इन भवनों का निर्माण स्कूल, धर्मशाला आदि के नाम पर किया जाता है ताकि जनता को धोखा दिया जा सके. तीन गांव में ऐसे भवन निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया था. हमारी पार्टी ने जनता के बीच इस बात का पर्दाफाश किया कि यह धर्मशाला नहीं बल्कि आप लोगों के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस कैंपों का निर्माण है. तो जनता ने संगठित होकर एक गांव में उस भवन को ध्वस्त कर दिया.

शहीद यादगार सप्ताह मनाया गया

बलांगिर एरिया के तुरेकेला अंचल में 28 जुलाई शहीद सप्ताह दमन के बीच सफलतापूर्वक मनाया गया. चार गांव के जनसंगठनों को बुलाकर मीटिंग की गयी जिसमें सौ से ज्यादा महिला व पुरुषों ने भाग लिया और शहीदों को सिर झुकाकर श्रधांजली अर्पित की. इस मौके पर लगभग ढाई हजार पर्चे-पोस्टरों और बैनरों से प्रचार किया गया. यह पर्चे-पोस्टर हिंदी और ओड़िया दोनों भाषाओं में थे. लाल कपड़े से शहीदों की स्मृति में शहीद वेदी का भी निर्माण किया गया.

दारु भट्टी ध्वस्त

1 अप्रैल को ग्राम डोगिंया और डोलमंदल में घासीराम अग्रवाल की दारु भट्टी को ध्वस्त किया गया. इस भट्टी को ध्वस्त कर वहां से एक एयरगन, सोलर पलेट, मोबाईल, कुल्हाड़ी सहित नकदी पैसा व कुछ अन्य सामान भी जब्त किया गया.

स्कूलों में मनाया गया झूठा स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रुप में एरिया के कई स्कूलों, आश्रम स्कूलों व हास्टलों में मनाया गया. वहां तिंरगा झंडा उतार कर विरोध का प्रतिक काला झंडा फहराया गया. इस मौके पर आजादी का पर्दाफाश करते हुए पर्चे, पोस्टर व बैनर भी तैयार किये गए. कई गांव के स्कूलों व आश्रम शालाओं में पुलिस ने डेरा डाल लिया था.

जमीन समस्या

बलांगिर एरिया में जमीनों पर ज्यादातर जमींदारों व सरकार का कब्जा है. इसके कारण से एरिया में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान मौजूद हैं. हर गांव में 40 से 50 प्रतिशत तक भूमिहीन लोग हैं. इनमें से ज्यादातर दलित व आदिवासी हैं. जमीन नहीं रहने के कारण इस इलाके में पलायन एक बड़ी समस्या है. लोगों को अपना घर-बार, बीबी-बच्चे छोड़कर प्रदेश में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है. इस समस्या को देखते हुए एरिया कमेटी ने विश्लेषण करते हुए एक गांव के 10 घरों में 30 एकड़ जमीन दिलवाने का निर्णय लिया.

एक दूसरे गांव में 40-45 घर हैं. उस गांव की जमीन को उन्हीं के गांव का गोटिया डेढ़ सिट जमीन को कब्जा करने के लिए साजिश रच रहा था. उसकी योजना थी पूरे गांव की जमीन पर कब्जा करके दूसरे लोगों को बेच देना. गांव की कमेटी ने निर्णय लेकर उस जमीन पर झंडा फहरा दिया. इस तरह की समस्या अन्य छह गांव में भी है. गांव में गोटिया लोगों का दबाव बहुत समय से चल रहा है.

साल भर विभिन्न समस्याओं, अवसरों पर चला प्रचार अभियान

2013 की पहली तिमाही में बलांगिर एरिया में कई विषयों पर पर्चे व पोस्टर छापे गए. आठ मार्च मनाने का आव्हान करते हुए, शहीद भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर, तेंदुपत्ता व अन्य वनोपजों का रेट बढ़ाने के लिए, केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए आव्हान पर फिलिपींस जनयुध्द के समर्थन में,

बचा हुआ पेज 19 पर

ओएसी स्टेटमेंट

सच्चे देशभक्तों से माओवादियों की अपील

अर्ध सैनिक बलों द्वारा सेना की मदद से चलाए जाने वाले आगामी फासीवादी सैनिक दमन अभियान के विरोध में

26 जनवरी 2014 - गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रुप में मनाओ!

देश की सेना को - देश की ही जनता के खिलाफ उतारने के विरोध में आवाज उठाओ!

देश की खनिज संपदाओं को विदेशी कंपनियों व दलाल पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए ही ऐसे सैनिक अभियान चलाए जा रहे हैं!!!

सच्चे देशभक्त जनवाद प्रेमियो देश के शोषक-शासक वर्ग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने और संसदीय पार्टियां आगामी विधानसभा व संसदीय चुनावों की तैयारियां जोरशोर के साथ कर रही हैं. हमारे देश को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में प्रचारित किया जाता है. हरेक देशवासी देश को सच्चे दिल से प्रेम करता है, सैनिक भी देश की रक्षा करने की कसमें खाते हैं. लेकिन सच्चाई क्या है - लोकतंत्र एक ढकोसला है और संविधान एक छलावा मात्र क्योंकि शोषकों ने अपने ही देश की जनता पर युध्द छेड़ा हुआ है. किसान-मजदूरों के सैनिक बेटों को देश के मध्य भाग में अपने ही लोगों के खिलाफ युध्द करने के लिए रवाना किया जा रहा है. जिस सेना को सरहदों की रक्षा करनी चाहिए आज उसे देश की सीमा पर नहीं देश के अंदर जंगलों में, निर्धनत्म आदिवासियों पर गोलियां बरसाने के लिए तैनात किया जा रहा है. शासक खुद अपने संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं.

26 दिसंबर 2013 को आपरेशन ग्रीनहंट 'जनता पर युध्द' का तीसरा चरण शुरु हो गया है. इस दिन 40 हजार अर्ध सैनिक बलों के नेतृत्व में और वायु सेना के दर्जनों सैनिक मिग-17 हेलिकाप्टरों, ड्रोन विमानों, राकेट लांचारों, जीपीएस सेटों आदि अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर चार दिन का एक सैनिक अभियान चलाया गया था. यह पहला मौका था जब देश की जनता के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर बाकायदा घोषणा करके युध्द का ऐलान किया गया. यह एक देशव्यापी हमला था, जिसने अंदुरुनी हिस्सो में जनजीवन में दहशत फैलाई और जनता को अपने दैनिक कामकाज निपटाना भी मुश्किल हो गया. और अब 14 जनवरी 2014 को फिर सीआरपीएफ के डीजीपी ने ओड़िशा आकाशवाणी समाचारों में घोषणा की है कि पहला अभियान सफल रहा अब एक लाख की संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात कर अभियान चलाया जायेगा, ताकि माओवादियों पर दबाव डाला जा सके और वह आत्मसमर्पण करके वार्ता के लिए आगे आ सकें. उसका कहना है कि इस नए अभियान से माओवादियों की कमर तोड़ दी जायेगी. सच्चाई यह है कि चालिस हजार की संख्या से चलाया गया दमन अभियान पूरी तरह से विफल हुआ है. हमारी पार्टी की जनता ने भरपुर मदद की जिस कारण से सैनिक बलों को कोई सफलता नहीं मिली. इसलिए दोबारा फिर उन्हें एक नए दमन अभियान को शुरु करने की घोषणा की है.

इस ऐलान से पहले ओड़िशा के मुख्यमंत्री व विदेशी कंपनियों के दलाल नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि कोरापुट, बलांगीर, बरगढ़, मलकानगिरी, कालाहांडी, रायगढ़, सुंदरगढ़, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, संबलपुर जिलों में माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं. माओवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. और अभी-अभी दक्षिण कोरिआई प्रधानमंत्री भी देश के दौरे पर हैं, जिसके साथ बड़े पूंजीपतियों का दल भी है. इसमें पोस्को कंपनी का अध्यक्ष भी आया हुआ है. यह वही कंपनी पोस्को है जो ओड़िशा में कई सालों से जनता के विरोध के बावजूद खदान खोलने पर आमदा है और इतना ही नहीं केंद्र व राज्य सरकारें उसके लिए लाल कालीन बिछा रही हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने भी उसको एक दिन पहले मंजूरी दे दी है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद रमन सिंग भी जीत के नशे में चूर होकर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए विदेशी कंपनियों का जोर शोर के साथ स्वागत कर रहा है.

आज हर सच्चे देशभक्त का कर्तव्य बन जाता है कि इस घटनाक्रम को समझे कि क्यों लाखों जनता की कुर्बानी की बदलौत जिन विदेशी कंपनियों को भगाया गया था उनका देश के शोषक-शासक वर्ग स्वागत कर रहे हैं और क्यों सैनिक अधिकारी अपनी ही जनता पर अंग्रेजों की तरह जुल्म ढहाने के लिए सैनिक अभियान की घोषणा कर रहे हैं.

हमारी राज्य कमेटी इस फासीवादी दमन अभियान का कड़ा विरोध करती है. शासक वर्गों को चेतावनी देती है कि वह माओवादी पार्टी को सरेंडर करवाने के ख्याली पुलाव न पकाये. आखिरी सांस तक जनता की जन सेना के योध्दा उसकी व उसके आंदोलन की रक्षा करेंगे. जनता की व्यापक मदद से इस तरह के अभियानों को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है. सलवा जुडूम इसका ताजा उदहारण है.

दोस्तो

आज पूरा देश जानता है कि माओवादी संघर्षरत इलाके आदिवासी बहुल इलाके हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड हो या ओड़िशा सभी खनिज संपदाओं के अकूत भंडारों से भरे हुए राज्य हैं. यहां की आदिवासी जनता पूरी तरह से जल-जंगल-जमीन पर निर्भर है. हमारे राज्य ओड़िशा में कदम-कदम पर बॉक्साईट, लोह और गरेफाइट आदि के भंडार हैं. पूरे राज्य को नवीन पटनायक बेच चुका है, इस संपदा को निकलाने के लिए टाटा, बिड़ला, वेदांता, पोस्को, स्टारलाईट, सेल आदि कंपनियों से एमओयू कर चुका है. काशिपुर, जगतसिंगपुर, नियमगिरी सहित पूरे राज्य में जनता विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत है. नियमगिरी के आसपास चार ब्लॉकों में 10 से ज्यादा कंपनियों से एमआयू हुए हैं जिनमें वेदांता भी एक है. वेदांता की नियमगिरी में हार के बाद उसे इसी के आसपास कुंडनमाली व सुजीमाली (पहाड़) को देने की मंजूरी राज्य व केंद्र सरकार ने दी है. नियमगिरी के बाद गंदमर्दान पहाड़ बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार है जहां पर 213 मिलियन टन बॉक्साइट है. आने वाले समय में कालाहंडी व रायगढ़ विदेशी कंपनियों व दलाल पूंजीपतियों के सबसे बड़े लूट के केंद्र बनने वाले हैं. इन दो जिलों में 40 से ज्यादा कंपनियों से राज्य सरकार ने एमओयू साइन किये हैं. आज सभी ये भी जानते हैं कि आर्थिक संकट के चलते सभी बड़ी-बड़ी विदेशी व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, इसलिए उनको अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए सस्ता कच्चा माल चाहिए और वह छीपा हुआ है आदिवासी इलाकों, आदिवासी इलाकों में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता यह देने के लिए तैयार नहीं है. आदिवासी जनता यहां सच्चे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है. काशिपुर, जगतसिंगपुर आदि में टाटा, हिंडालको वर्षों से जनता का दमन कर रहे हैं, नियमगिरी में वेदांता के मंशूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और पोस्को को भी खाली हाथ बैठना पड़ रहा है. इसलिए बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर उनसे मोटी दलाली लेकर ओड़िशा की नवीन पटनायक सरकार की तरह सभी राज्यों की सरकारें व केंद्र की यूपीए-2 जनता पर युध्द लाद रही हैं. इसलिए तमाम देशभक्तों को समझ लेना चाहिए है कि यह युध्द देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के मुनाफ के लिए लड़ा जा रहा युध्द है. यह युध्द देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं, देश के नागरिकों के खिलाफ लड़ा जाने वाला युध्द है. आज माओवादी ही नहीं विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाली जनता, अपनी जल-जंगल-जमीन के लिए लड़ने वाली आदिवासी जनता व उसका समर्थन करने वाली हर ताकत फासीवादी ग्रीनहंट के निशाने पर है. माओवादी संघर्षरत इलाकों में पहले से तैनात 3 लाख 50 हजार सशस्त्र बलों के अलावा और एक लाख सशस्त्र बलों की तैनाती से पूरी तरह देश को मनमोहन, चिदंबरम, सुशीलकुमार शिंदे, सोनिया गांधी, रमन सिंग व नवीन पटनायक जैसे लूटेरे युध्द में डूबो देना चाहते हैं. पता नहीं कितने सार्किनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहार करने पर आमदा हैं.

भाजपा, कांग्रेस, बिजू जनता दल तमाम पार्टियां चुनाव के लिए लोकलुभावने वायदे, घोषणाएं कर रही हैं. सभी संसदीय पार्टियां पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों की दलाल हैं. इसलिए आज जनता के खिलाफ युध्द व जनता के दमन के लिए देश की सेना की तैनाती पर एकमत होकर काम कर रही हैं. दमन के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को यह सहन नहीं कर पा रही हैं. बीजेपी प्रवक्ता हो या मोदी बुध्दिजीवियों की जनता के समर्थन में उठने वाली आवाज को सेना के जवानों का हौंसला तौड़ने वाली बता रहे हैं जैसे कि सेना सरहद पर दुश्मन देश की सेना के खिलाफ युध्द लड़ रही हो. जबकि स्पष्ट है कि यह युध्द अपनी ही देश की जनता के खिलाफ अपने ही देश के जंगलों और गांवों में लड़ा जा रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के गुस्से को भुना कर सत्ता में आए, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दंभ भरने वाले नेता भी आम आदमी के खिलाफ सेना की तैनाती पर मौन हैं, आम आदमी का जनसंहार हो रहा है, सेना, अर्ध सैनिक बलों व्दारा बलात्कार किये जा रहे हैं, आम आदमी के घर जलाये जा रहे हैं उसे विस्थपित किया जा रहा है, लेकिन वह इस सब पर चुप है, क्योंकि आम आदमी ऐसे नेताओं के लिए सत्ता पर चढ़ने की सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं होते.

सच्चे देशभक्तो

माओवादी पार्टी देश की सच्ची आजादी के लिए लाखों जनता का नेतृत्व करते हुए संघर्षरत है. उसने हजारों नेताओं, योध्दाओं, नौजवानों की शहादत ही देश की जनता की खुशहाली के लिए दी है. उसके नेतृत्व में जनता ने व्यापक इलाके में अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा की, कई विदेशी व पूंजीपतियों की कंपनियों की लूट से बचाया है. विस्थापन के खिलाफ एक बड़ी ताकत के रुप में उभरी है. वह इस शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक शानदार विकल्प प्रस्तुत कर रही है यही वजह है कि आज वह तमाम विदेशी कंपनियों, बड़े पूंजीपतियों व शोषक लूटेरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गयी है. इस लिए आप्रेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण को शुरू करते हुए इतने बड़े सैनिक अभियान की घोषणा शासकों ने की है.

इस युध्द की सफलता से पूरा देश एक बार फिर साम्राज्यवादियों, विदेशी कंपनियों का गुलाम बन जायेगा. देश की जनता अपने जल-जंगल-जमीन व खनिज संपदाओं से हाथ धो बैठेगी, तमाम जन आंदोलनों को सरकार कुचल डालेगी और पूंजीपतियों-सामंतों का एक छत्र राज कायम हो जायेगा. विरोध की हर आवाज दफन हो जायेगी.

इसलिए आज सभी नागरिकों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि वह इस युध्द के खिलाफ हैं या इसके समर्थन में. आज देशभक्तों को चाहिए कि विदेशी कंपनियों, पूंजीपतियों के फायद के लिए लड़े जाने वाले युध्द का विरोध करें. हम देश के तमाम नागरिकों, छात्रों, किसान-मजदूरों, दुकानदारों, बुध्दिजीवियों से अपील करते हैं कि इस अन्यायपूर्ण युध्द के खिलाफ 26#जनवरी 2014 के गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रुप में मनाएं.

सच्चे देशभक्त सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों से अपील करते हैं कि वह सरकार की साजिश को समझें, अपने ही देश की गरीब जनता पर युध्द में न उतरें, पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों के लिए बलि के बकरे मत बनें!

अर्ध सैनिक, सैनिक व पुलिस बलों के जवानों के माता-पिता व भाइ-बहनों से अपील है कि अपने बेटों को अपने ही भाईबंदों पर गोली चलाने से रोकें, देश की जनता के खिलाफ उनकी तैनाती के विरोध में एकजुट हो आंदोलन करें.

भारत के जनयुध्द के समर्थन में काम कर रही तमाम क्रांतिकारी, प्रगतिशील, आदिवासी शुभचिंतक ताकतों से हम अपील करते हैं कि इस तरह के अभियानों के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जनमत तैयार करें और ऐसे अभियानों की कड़ी भर्त्सना करें.

इंकलाबी अभिवादन के साथ

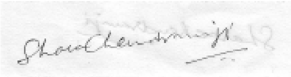

शरतचंद्र मांझी
प्रवक्ता
ओड़िशा राज्य कमेटी
भाकपा (माओवादी)

दिनांक: **15** जनवरी **2014**

श्रधांजली

कामरेड आकुला भूमैय्या को लाल सलाम!

तेलांगाना के जन नेता अकुला भूमैय्या की राजनीतिक हत्या की भर्त्सना करो!

भूमैय्या की हत्या नौकरशाहओं व सिमा आंध्रा के नेताओं की सुनियोजित साजिश का परिणाम है!!

तेलांगाना के वरिष्ठ जननेता अकुला भूमिया को सरकारी हत्यारों ने 24 दिसंबर की रात को हैदराबाद में बर्बरता के साथ मार डाला. भूमिया स्थानीय प्रेस क्लब बशीरबाग से तेलांगाना पर एक पुस्तक का लोकार्पण कर लौट रहे थे. रास्ते में एक षड़यंत्र के तहत नगर निगम की एक वैन विद्यानगर मे उसका इंतजार कर रही थी. पहले तो उस वैन ने उसके स्कुटर को टक्कर मारी फिर उसको रौंदते हुए चली गयी, जिस से उसकी मौत हो गयी. बाद में उस ड्राईवर को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया. मानवाधिकार संगठनों, कार्यकर्ताओं की जांच में पता चला है कि वह ड्राईवर नगर निगम की गाड़ी का ड्राईवर नहीं था, न ही कभी लोगों ने उसे देखा था. उसे हत्या करने के मकसद से ही किरणकुमार रेड्डी की सरकार व नौकरशाहों ने लगाया था. यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि तेलांगाना के जननेताओं की राजनीतिक हत्या है जो षड़यंत्र के तहत किरणकुमार रेड्डी सरकार व उसके अधिकारियों द्वारा की गयी है. उसे दुर्घटना का जामा पहनाया जा रहा है. भूमिया तेलांगाना प्रजा फ्रंट के अध्यक्ष थे जो अलग तेलांगाना राज्य के लिए संघर्षरत है.

आकुला भूमिया आंध्रप्रदेश में अध्यापक आंदोलन के प्रसिध्द नेता थे. उसने खुद को कभी मात्र अध्यापक आंदोलन तक सीमित नहीं रखा, 1960 से ही वह तेलांगाना की जनता के सामाजिक व क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते थे. वह केवल अलग तेलांगाना के लिए ही नहीं लड़ रहे थे बल्कि तमाम शोषित-पीड़ित जनता, आदिवासी-दलितों के हितों की रक्षा के लिए भी वह लड़ाई लड़ रहे थे. उनका जन्म 1948 में करीमनगर जिला, पेद्दापल्ली ब्लॉक के गांव काबापुर में हुआ था.

उन्होंने न केवल तेलांगाना में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विश्व व्यपार संगठन के खिलाफ बने जेएएफआईएफ में, साम्राज्यवाद-भूमंडलीकरण के खिलाफ बने संगठन एफआईएजी में, 2004 में एमआर-2004 के आयोजन सहित पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया-पीडीएफआई के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

आंध्र प्रदेश में क्रांतिकारियों की साजिश पूर्वक हत्याओं, झूठी मुठभेड़ों, काले गिरोहों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं का इतिहास बहुत पूराना है. किरणकुमार रेड्डी की सरकार भी उसे फासीवादी तरीके से आगे बढ़ा रही है, न केवल माओवादी समर्थक, जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं को बल्कि अलग तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं को बर्बरता के साथ कतल कर रही है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की ओड़िशा राज्य कमेटी कामरेड गंटी प्रसाद व कामरेड आकुला भूमिया की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करती है. और कामरेड गंटी प्रसाद व आकुला भूमिया को लाल श्रधांजलि अर्पित करती है.

कामरेड गंटी प्रसाद हमेशा जिंदा रहेंगे!

रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के उपाध्यक्ष, कमेटी फॉर द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मार्टियर्स के कार्यकारी सदस्य और विप्लवी रचयितलु संघम (विरसम या रिवॉल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन) से जुड़े गंटी प्रसादम पर चलाई गई गोलियां और तलवार के वार इसके सबूत हैं कि शासक वर्ग हमेशा इतिहास को भुला देता है.

वह भुला देता है कि अपने औपनिवेशिक कब्जे के लगभग 400 वर्षों के दौरान स्पेनी हत्यारों ने लातिन अमेरिका में दसियों लाख मूल निवासी इंडियनों की हत्याएं कीं, लेकिन जब 01 जनवरी 1899 को क्यूबा की आजादी के साथ लातिनी अमेरिका से आखिरी स्पेनी सैनिक स्पेन के लिए रवाना हुआ, तब 6 करोड़ से ज्यादा लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए जिंदा थे.

वह भुला देता है कि समाजवाद को उसकी पैदाइश के वक्त ही दम घोंट कर मार देने के मकसद के साथ 1918 की गर्मियों में सोवियत संघ में उतरे 13 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को दो साल के बाद हजारों मौतों और नुकसानों को अपनी झोली में डाले, नाकामी की शर्मिंदगी लेकर लौट जाना पड़ा था.

1945 से लेकर अब तक अमेरिका ने 40 विदेशी सरकारों का तख्तापलट करने की कोशिश की है, 30 से ज्यादा लोकप्रिय और चुनी हुई सरकारों को गिराया है और 25 से ज्यादा देशों पर बम गिराए हैं. इस सारी कोशिश में उसने बीसियों लाख लोगों और हजारों राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं. लेकिन वह भुला देता है कि इतना कुछ करने के बावजूद स्थिरता के लिहाज से और भविष्य के लिहाज से वह दुनिया के इतिहास का सबसे कमजोर साम्राज्य है. जिन देशों को उसने भारी फौजी बूटों के नीचे दबा रखा है, वह उनके बारे में भी पूरे भरोसे के साथ कुछ नहीं कह सकता. इस वक्त, जिस तेजी से आप इन अक्षरों को पढ़ रहे हैं, उससे दोगुनी तेजी से, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ दुनिया भर में चल रही अवामी जंग के हिस्से के बतौर साम्राज्यवाद के किलों पर गोलियां दागी जा रही हैं.

ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को सूरज उगने से भी पहले तीन नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया था. इस जुर्म में दुनिया भर में मशहूर कर दिए गए अहिंसा के कथित पैगंबर की भी सहमति थी. लेकिन आज, आठ दशक बीतने के बाद भी वे तीनों नौजवान इतने खतरनाक हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उनके लेखों, बयानों और चिट्ठियों वाली किताबें खरीदने और बेचने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे लागू करने पड़ते हैं. उनमें से एक नौजवान का चेहरा इस देश में विरोध में तनी हुई हर मुट्ठी में से झांकता है: भगत सिंह का चेहरा.

28 जुलाई 1972 को जिस देश के एक अदना से थाने में पुलिस हिरासत में चारू मजुमदार को मार डाला गया, उसी देश के प्रधान मंत्री को चार दशकों के बाद यह ऐलान करना पड़ा कि चारू के सपनों और मकसद को अपने कंधों पर ढोने वाला, दुनिया के सबसे निर्धनतम और सबसे उत्पीड़ित तबका संपत्ति और लूट की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है.

शासक वर्ग इतिहास को भूल जाए तो भूल जाए, इतिहास उसे कभी नहीं भूलता.

कल जिस जिंदगी को खत्म कर दिया गया, क्या उसकी ताकत को कोई खत्म कर पाएगा? उसकी जला दी गई आखिरी हड्डी के साथ, सड़क से लेकर अस्पताल के बिस्तर तक बहे खून की आखिरी बूंद के साथ, गुजरते हुए पल के साथ बुझ रही आखिरी सांस के साथ, कितने नारे, कितने संघर्ष, कितनी कहानियां, कितनी यातनाएं, कितने मोर्चे और कितने सपने होंगे, जिन्हें खत्म किया जा सकेगा? क्या सचमुच? क्या सचमुच कोई गोली ऐसी बनी है, जो कहानियों का कत्ल कर सके? कविताओं का? सपनों का? नारों का? विचारों का?

उनके आखिरी कदम एक शहीद के परिजन को अस्पताल में देखने जाने के लिए उठे थे. आज हम उनकी शहादत को सलाम करने जा रहे हैं.

संघर्ष और इंसाफ की उस आवाज को सलाम. आने वाले दिनों में, जब खेतों में पसीना बहाते किसानों और कारखानों में पिसते मजदूरों, मुसलमानों और दलितों, पिछड़ों, औरतों तथा उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं-उत्पीड़ित जनता-का कारवां लड़ाई के मोर्चे से जीत के नारों के साथ लौटेगा और अपने फौलादी सपनों और अपनी जीत के झंडों के साथ सड़कों और गलियों को, खेतों और कारखानों और वादियों और जंगलों को भर देगा, और जिन शहादतों को सबसे पहले याद किया जाएगा और सलामी दी जाएगी, तब किसी को गंटी प्रसादम के नाम की याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

और उसके बाद भी, सारे जमाने के सभी शहीदों की तरह, वे जिंदा रहेंगे. कॉमरेड गंटी प्रसादम. लाल सलाम साथी.

यह लेख एक बलॉग पर स्वतंत्र पत्रकार ने पोस्ट किया था,

प्रर्चा

तेंदुपत्ता सहित तमाम लघु वन उत्पादों और जंगल पर अधिकार जनता का है :सरकार का नहीं!

टाईगर रिजर्व एरिया के हर गांव में फड़ खुलवाने के लिए संघर्ष तेज करो!

प्रति सैकड़ा गड्डी ओड़िशा में 160 व छत्तीसगढ़ में 170 रुपये की मांग करो!

प्रिय ग्रामवासियो!

लगभग तीस सालों से सितानदी, उदंती और ओड़िशा के सोनाबेड़ा को टाईगर रिजर्व घोषित कर जनता के तमाम अधिकार सरकार ने छीन लिए. जिस जंगल पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, जन्म से लेकर मृत्यू तक हर काम जंगल से जुड़ा हुआ है. सदियों से हमारे पूर्वज इस जंगल की रक्षा करते आ रहे थे. जानवर और इंसान हमेशा साथ-साथ रहते आए थे. लेकिन सरकार ने जंगल पर कब्जा करने के इरादे से इसको टाईगर रिजर्व घोषित किया. जंगल से बांस, तेंदुपत्ता, लाख, महुआ, टोरा आदि जमा करना अपराध बना दिया गया है.

आदिवासी इलाकों में बांस, महुआ, तेंदुपत्ता जैसी वनोपज जनता के लिए कृषि के बाद आमदनी का मुख्य स्रोत है. लेकिन सरकार ने इस टाईगर रिजर्व से जनता के आर्थिक स्रोत को इसलिए बंद किया ताकि जनता मजबूर होकर यहां से खुद ही भाग जाए.

2006 में वन अधिकार कानून बनाकर खुद सरकार ने जनता को अधिकार दिया कि

- ग्रामवासियों को लघु वनोपज को उपभोग करने व बेचने का अधिकार है. यानि तेंदुपत्ता, बांस, लाख, पत्ते, शहद, जड़ी-बुटियां, इमली, आवंला, जलाउ लकड़ी आदि तमाम वनोपज पर जनता का अधिकार है.

- तेंदुपत्ता जिसका व्यापार अनेक राज्यों में वन निगमों द्वारा एकाधिकार किया गया है, वह वन अधिकार कानून की आत्मा के विपरीत है एवं यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए.

जनता को वनोपज का मूल्य बढ़ाने का भी अधिकार है यहां तक कि ग्राम सभा टीपी (ट्रांजिट परमिट) लेने की भी जरूरत नहीं है. लघु वनोपज को खरीदने, बेचने पर कोई फीस/शुल्क/रायल्टी लगाना कानून का उल्लंघन होगा.

टाईगर रिजर्व एरिया एवं अभ्यारण्यों में रहने वाले लोगों के बारे में भी पेसा कानून 1996 में भी उल्लेख किया गया है और वन अधिकार कानून 2006 में स्पष्ट किया गया है कि टाईगर रिजर्व व वन अभ्यारण्यों ग्रामों को भी इस कानून के तहत तमाम अधिकार आदिवासी व अन्य पारंपरिक वन निवासियों को देने होंगे. बाद में जरूरत पड़ी तो लोगों को विस्थापित करने से पहले केंद्रीय विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर उन लोगों का पुनर्वास या वैकल्पिक पैकेज/केंद्रीय कानून नीतियों के तहत तैयार होगा और इसकी सूचना लोगों को देनी होगी.

इसके साथ-साथ वन अधिकारियों को 1927 के वन कानून में बंदोबस्त के प्रावधान के अनुसार यह अधिकार है कि जनता की मांग पर लघु वनोपजों के उपयोग करने, संग्रहण करने की इजाजत दें.

लेकिन सरकार क्या कर रही है? सीतानदी-उदंती-सोनाबेड़ा टाईगर रिजर्व और अभ्यारण्य के नाम पर आज तक जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रख रही है. तेंदुपत्ता या अन्य लघु वनोपज पर टीपी का अधिकार तो क्या सरकार लघुवनोपजों का संग्रहण तक नहीं करने दे रही है. जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जय रामरमेश हर रोज अखबारों, टीवी, रेडियो में वन अधिकार कानूनों का ढोल पीटता रहता है. छत्तीसगढ़ में जिन तेंदुपत्ता सहकारी समितियों से तेंदुपत्ता संग्रहण करवाया जा रहा है वह भी पूरी तरह से गैर कानूनी हैं, सरकार हमारे जंगल, वनोपजों की ठेकेदारों से रायल्टी लेती है वह भी गैर कानूनी है. कानून कहता है कि तेंदुपत्ता सहित तमाम वनोपजों पर संपूर्ण अधिकार जनता का है तो वह करोड़ों की रायल्टी सरकार क्यों ढकार रही है. जब तेंदुपत्ता के दाम तय करने का अधिकार जनता को दिया गया है तो क्यों हर साल सरकार ही रेट तय करती है? सरकार बोनस के नाम पर घटीया जूते, चप्पल आदि बांट कर करोड़ों की रायल्टी हड़प रही है. और ठेकेदारों के साथ सांठगांठ तेंदुपत्ता तोड़ाई का रेट कम रखती है. एक तरफ रायल्टी व ठेकेदारों से रिश्वत खाती है तो दूसरी तरफ जूते, चप्पल बनाने वाली कंपनियों से सांठगांठ कर भ्रष्टाचार करती है.

इसलिए हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि तेंदुपत्ता कारोबार में घुसकर, उसको गैर कानूनी तरीके से चला कर भ्रष्टाचार बंद करे, और जनता को तेंदुपत्ता तोड़ाई का वाजिब रेट मुहैया करवाये. बोनस का लालीपॉप थमाना छोड़ कर संपूर्ण अधिकार जनता को दे.

जनता से हमारी अपील है कि टाईगर रिजर्व में फड़ी खुलवाने की मांग करना, उसके लिए संघर्ष करना गैर कानूनी नहीं है. न ही ऐसा कोई कनूनी प्रावधान है कि टाईगर रिजर्व में फड़ी नहीं खुल सकती. असल बात तो यह है कि टाईगर रिजर्व और अभ्यारण्य ही गैर कानूनी हैं. इसलिए समस्त जनता को चाहिए कि वह टाईगर रिजर्व एरिया में फड़ खुलवाने के लिए वन विभाग व राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंके. माओवादी पार्टी आपके साथ है.

जहां पर माओवादी पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष तेज है वहां पर जनता ठेकेदारों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी वनोपजों के वाजिब दाम प्राप्त कर रही है. चाहे बस्तर हो या कांकेर, राजनांदगांव, लेकिन जहां पर जनता संघर्ष नहीं कर रही उसे राज्य सरकार व ठेकेदार लूट रहे हैं. पीछले साल कांकेर जिला के बांदे क्षेत्र में 190 रुपये प्रति सैंकड़ा ठेकेदारों को रेट देने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि जनता ने जम कर संघर्ष किया. इसलिए आप भी इस साल छग में 170 रुपये और ओड़िशा में 160 रुपये प्रति सैकड़ा के लिए रेट का ऐलान करें.

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

मैनपुर-नुवापाड़ा डिवीजनल कमेटी **भाकपा (माओवादी)**

जवाब

गरियाबंद पुलिस प्रशासन के बेबुनियादी और झूठे प्रचार को ठोकर मारो!

प्रिय जनता

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनता पर जारी युध्द आपरेशन ग्रीनहंट के तहत माओवादियों को खत्म करने का नाकाम प्रायस करते पीछले दिनों गरियाबंद पुलिस ने अभियान चलाया और हमारे एरिया में दुश्प्रचार युध्द के तहत पर्चे फैंके. गरियाबंद पुलिस के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद ही नहीं झूठे भी हैं.

गुडसा उसेंडी का सच

पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर आरोप जनता व पार्टी के प्रति गद्दारी करने वाले गुडसा उसेंडी के हवाले से लगाए हैं. गुडसा उसेंडी के हमारी पार्टी के साथ कोई सैध्दांतिक मतभेद नहीं थे. न ही उसने कभी अपने अंतरविरोधों को पार्टी कमेटियों के सामने रखा था. उसने जीरमघाटी हमले, स्कूलों को गिराये जाने, 'निर्दोषों' को मारे जाने, महिलाओं के शोषण के उपर कई बार शासकों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का खंडन किया था. लेकिन आज वह वही भाषा बोल रहा है जो आंध्र प्रदेश का विशेष खुफिया विभाग यानि एपीएसआईबी बुलवा रही है. वह उनके हाथों बिक गया है. दरअसल गुडसा उसेंडी का नैतिक पतन हो चुका था. जिस महिला को लेकर सरेंडर हुआ वह उसकी पत्नि नहीं है. उस महिला से कामरेड उसके अवैध संबंध थे, उसका नाम संतोषी मरकाम है. सब जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचारों करने वालों पर माओवादी पार्टी कड़ी कार्रवाई करती है. गुडसा उसेंडी की गलती बाहार आ गयी थी. इसलिए वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से आंदोलन से ही भाग खड़ा हुआ ताकि बहार आराम और ऐश परस्ती की जिंदगी जी सके. अब वह अपनी गलती को छुपाने के लिए माओवादी पार्टी झूठे आरोप लगा रहा है. और उससे भी बड़ी बेशर्मी गरियाबंद पुलिस कर रही है - जो व्यक्ति अपनी पत्नि को छोड़कर दूसरी महिला को भगा कर ले गया, अवैध संबंध रख कर अनैतिक कार्य किया ऐसे पतीत व्यक्ति को आदर्श के रुप में पेश कर रही है. वह जनता व अन्य कैडर को भी वैसा ही पतीत व महिला विरोधी व्यक्ति बनने की शिक्षा दे रही है.

पहली झूठ - माओवादी महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं!

सच - हम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन भी मानते हैं कि माओवादी आंदोलन में महिलाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं. माओवादियों में 47 प्रतिशत तक महिलाएं हैं, न केवल नीचले कमांडर स्तर पर बल्कि उपरी कमेटियों में भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी है. अगर हम महिलाओं का शोषण करते तो क्यों इतनी संख्या में महिलाएं पार्टी में भर्ती होती! सच्चाई यह है कि पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने सैकड़ों से ज्यादा महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ में, दर्जनों महिलाओं के साथ ओड़िशा के बलांगिर, मलकनगिरी, कोरापुट जिलों में और सैकड़ों महिलाओं के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों व कश्मीर में सामूहिक बलात्कार किये हैं. कुंबिंग ऑपरेशनों के दौरान पुलिस व अर्ध सैनिक बल गांव की महिलाओं के साथ सरेआम छेड़खानी करते हैं. जंगलवार कॉलेज कांकेर के गांव पात्थरी की महिलाएं उसे वहां से उठाने के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं. पुलिस के रंगरुट गांव में घुसकर महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं. शौच के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं को उठाकर उनसे बलात्कार करते हैं. गांव की महिलाओं का अकले निकलना मुश्किल हो गया है. ऐसा ही हाल सभी पुलिस थानों व कैंपों के गांव का है. उस पुलिस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिस ने एक सरकारी शिक्षिका सोनी सोडी के साथ हिरासत में एसपी के नेतृत्व में बलात्कार किया और उतना ही नहीं मानवता को शर्मसार करते हुए, बर्बर व पाश्विक तरीके से उसकी योनि में पत्थर तक डाल दिये. इसकी रिपोर्ट कलकता के एक हस्पताल में जांच के बाद जारी की. ऐसा कुकृत्य करने वाले अंकित गर्ग को राष्ट्रपति ने पदक से नवाजा, पुलिस ने पदोन्नति दी! अब वही पुलिस नैतिक रुप से पतीत हो चुके गुडसा उसेंडी को आदर्श के तौर पर पेश कर रही है. तो पहचानीये माहिलाओं का शोषण कौन करते हैं माओवादी या पुलिस?

दूसरा झूठ - माओवाद से विकास के रास्ते बंद हो रहे हैं, बिजली, शिक्षा और ईलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है! सड़कें नहीं बन रही हैं!

सच - विकास के विरोधी माओवादी नहीं हैं, दरअसल सरकार और पुलिस बड़े पूंजीपतियों, जमींदारों और विदेशी कंपनियों के फायदे को ही विकास समझती है. छत्तीसगढ़ में हजारों किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है. प्रति एक किलोमीटर सड़क के लिए डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया गया है. और सरकार के विधायक खुद सच्चाई उगल रहे हैं कि बस्तर की 32 लाख की आबादी के लिए 100 एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है! राज्य में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां शिक्षकों की संख्या पूरी हो. बिजली का निजीकरण कर दिया गया है. राज्य की बिजली को पूंजीपतियों को कौड़ियों के मोल दिया जाता है, जबकि किसानों को बिजली की आपूर्ति मात्र छः घंटे, वह भी लगातार नहीं की जाती जिस कारण किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं. प्रति दिन एनएमडीसी 85 करोड़ रुपये बैलाडिला खदान से कमाती है लेकिन साल में एक दिन की कमाई भी जनता के विकास के लिए नहीं खर्च करती. ऐसा ही हाल अन्य कंपनियों का है! तो क्या माओवादी विकास के विरोधी हैं? आदिवासी इलाकों को बरसों से लूट रही सरकार को माओवादी पार्टी के आंदोलन के बाद ही 'विकास' की बात याद आई. उससे पहले सरकार कहां थी? क्यों पुलिस-फोर्स पर हजारों करोड़ रुपाये खर्च

किये जा रहे हैं और क्यों राज्य के 60 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. क्यों कर साल डेढ हजार के आसपास किसान आत्महत्या कर जाते हैं? किसके विकास के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि निजी कंपनियों को दे दी गयी और किसके विकास के लिए सितानदी, उदंती से लेकर आमामोरा तक आदिवासी व किसानों को उजाड़कर टाईगर परियोजना पर अमल किया जा रहा है?

तीसरी झूठ - ग्रामीणों द्वारा माओवादी नक्सलियों का विरोध

सच - यह एक और सफेद झूठ है. पुलिस ने इसे सच्च जैसा समझाने के लिए दो फोटो भी छाप दिये हैं. पुलिस का कहना है कि ओड़िशा के सोनाबेड़ा और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के ढुठीअंबा गांव के लोगों ने माओवादियों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं. गांव सोनाबेड़ा में नुआपाड़ा के एसपी उमाशंकर दास ने मुखबिरों का नेटवर्क बनाया था. उसने कुछ को तो गैरकानूनी तरीके से एके-47 जैसे घातक हथियार भी दिये थे ताकि माओवादी नेताओं को मारा जा सके. जनता में इसका पर्दाफाश हुआ. दो मुखबिरों को पकड़कर माओवादी पार्टी ने एक का सफाया कर दिया जबकि एक को जनता के कहने पर माफ कर दिया था. अपने मुखबिर नेटवर्क को बचाने के लिए मुखबिरों के जरिये एसपी ने जनता को भड़काया लेकिन जल्द ही जनता को इस साजिश का पता चल गया. पुलिस ने इसको आधार बनाकर जबरन उस गांव में कैंप डाल दिया. यही पुलिस का लक्ष्य भी था. पुलिस मुखबिरों का जीते जी सुचना जमा करवाकर फायदा उठाती है, उनके खत्म होने पर 'आम जानता को नक्सलियों ने मारा' कहकर दुश्प्रचार कर फायदा उठाती है. इस प्रकार पुलिस को दोनों तरीके से फायदा है, जबकि बलि का बकरा बनते हैं मुखबिर!

ढुठीअंबा गांव की जनता ने माओवादियों के खिलाफ नहीं पुलिस के खिलाफ ही हथियार उठाये हैं. इसकी सच्चाई समझीये - माओवादी पार्टी से कुछ भागे और सरेंडर कर चुके नकली नक्सली - पीएलएफआई, जेपीसी, टीपीसी आदि टोलियां बनाए. अब वह लोग पुलिस के साथ मिलकर जनता, पूंजीपतियों, दुकानदारों आदि से बंदूक दिखाकर पैसे वसूलते हैं, इसमें थाने दार से लेकर एसपी तक का हिस्सा होता है. इस साठगांठ से जनता परेशान हो चुकी है. नकली नक्सलवादियों की आड़ में हमारी पार्टी के खिलाफ दुश्प्रचार किया जा रह है जबकि वह लोग पुलिस के ही लोग होते हैं. इसलिए जनता ने भाकपा (माओवादी) के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस के टटटुओं के खिलाफ हथियार उठाये हैं. हम जनता की इस पहल का समर्थन करते हैं. और अपील करते हैं कि पुलिस व नकली नक्सलियों के गठजोड़ का पर्दाफाश कर उन्हें मार भागएं.

प्रिय जनता, किसान-मजदूरों, छात्र-नौजवानों, माताओ-बहनों, दुकानदार-व्यापारियों, कर्मचारी-बुध्दिजीवियो आप सबसे हमारी पार्टी की अपील है कि गरियाबंद पुलिस के इस झूठे प्रचार को सिरे से खारिज कर ठोकर मार दो. माओवादी पार्टी के खिलाफ पुलिस की साजिशों का पर्दाफाश करें, पुलिस की अनैतिक असामाजिक शिक्षा की भर्त्सना करे!

नोटा के धोखे से बचके बाबा!

नोटा हो या वोट बटन दोनों का मतलब है लाइसेंस देना कि - 'लूटो मुझे और पांच साल के लिए'

इस बटन की शुरुआत 2013 नवंबर में हुए पांच राज्यों की विधानसभा के चुनावों की गयी है. लोकसभा चुनावों में भी यह बटन रहेगा. लेकिन इसका प्रचार नहीं किया जा रहा.

संसदीय चुनावों से जनता का विश्वास धीरे-धीरे घटता गया. जनता ने चुनावों में भाग लेना ही छोड़ दिया. परिणाम स्वरूप पचास प्रतिशत से भी कम मतदान होता था. इस लोकतंत्र के मुखोटे को बचाने के लिए, और कुछ प्रगतिशील शक्तियां जीते हुए उम्मीद्वार को वापस बुलाने के अधिकार के लिए लड़ रही थीं. वहीं संघर्षरत इलाकों की जनता ने तो सिरे से ही इन चुनावों को खारिज कर चुनावों के बहिष्कार का नारा बुलंद किया हुआ है. जनता के उठते विश्वास को फिर से कायम करने के लिए, जनता की चुनावों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए नोटा बटन को सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने मशीनों में लगाया है. नोटा बटन पूरी तरह से शक्तिहीन है क्योंकि जीतने वाले उम्मीद्वार से ज्यादा वोट भी नोटा बटन पर गिर जायें तो वहां के चुनाव रद्द नहीं होते न ही वह उम्मीद्वार हारा हुआ माना जाता. कुल मिलाकर यह जनता को गुमराह करने वाला बटन है और कुछ नहीं!

कुछ पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था है कि अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट उम्मीद्वार को न मिले तो उसकी जीत नहीं मानी जाती. लेकिन भारत के महान 'लोकतंत्र' 55 प्रतिशत ही वोट डाले, उसमें से भी उम्मीद्वारों की संख्या दर्जनों में अगर एक मतदाता को 10 प्रतिशत वोट भी मिले तो उसकी जीत मानी जाती है और उसे जनता का प्रतिनिधि बताया जाता है!

'भारत के राजनीतिक बंदी हमारे बंदी हैं - भारत के शहीद हमारे शहीद हैं'

नारे के साथ भारत के राजनीतिक बंदियों के साथ एकजुटता व संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया गया!

भारतीय जनयुध्द के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कमेटी (आईसीएस-पीडब्बलू) के आव्हान पर पूरी दुनिया में भारत के राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई व उनको जेलों में दी जा रही अमानीवय यातनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया. दुनिया की प्रगतिशील, जनवादी, माओवादी, क्रांतिकारी ताकतों ने भारत को 'जनसंघर्षों के जेलखाने' के तौर पर चिन्हित करते हुए भारत के शासक वर्गों द्वारा जनआंदोलनों के दमन के लिए चलाए जा रहे बर्बर व हिंसक आपरेशन ग्रीनहंट का विरोध किया और भारत सरकार से मांग की कि तुरंत क्रांतिकारी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा किया जाये. इस दिवस को मनाने से पहले कई देशों में जोरों से प्रचार अभियान भी चला.

हम उन कामरेडों के पक्ष में हैं
जो क्रांतिकारी जनयुध्द का दिल बनी हुई हैं!
बिना शर्त तमाम राजनीतिक बंदियों को रिहा करो!

सर्वहारा क्रांतिकारी नारीवादी आंदोलन - इंटली की स्टेटमेंट

कहने को तो भारत 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' है लेकिन वहां की सरकार, सशस्त्र बल और संसद महिलाओं के साथ बलात्कार को, जनता के उपर युध्द को बर्बर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं. भारत के ज्यादातर इलाकों में, शहरों में और खासतौर से उन इलाकों में जहां जनयुध्द चल रहा है महिलाओं के साथ सशस्त्र बलों द्वारा बलात्कार, हत्याएं आम बात बनी हुई है. इतना ही नहीं जब महिलाएं पुलिस की हिरासत में होती है तब भी उनको यातनाएं दी जाती हैं.

भारतीय प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी राज्य दरअसल महिलाओं की जनयुध्द में व्यापक भागीदारी से डरा हुआ है और वह किसी भी कीमत पर इस भागीदारी को रोकना चहता है.

बहुत सारी बहादुर व दृढ़ महिलाएं आज बंदी हैं, उनकी हालात आज बुरी है, जेलरों द्वारा हिंसा व बलात्कार किये जाते हैं.

आयरलेंड की राजधानी दुबलायन में
भारतीय दुतावास के बाहर प्रदर्शन का आयोजन

भारतीय दुतावास के बाहर आयरिश रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिक नेटवर्क फॉर यूनिटी, 1916 सोसाइटी, रिपब्लिकन सिन्न फिन, द दुबलायन इंटरनमेंट कमेटी सहित जनवादी, साम्राज्यवाद विरोध व माओवादी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ व राजनीतिक बंदियों के समर्थन में एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया.

उन्होंने भारतीय दुतावास को आयरिश जनता की तरफ से एक मांगपत्र भी सौंपा जिसमें भारत सरकार से मांग की गयी थी कि आपरेशन ग्रीनहंट को तुरंत बंद किया जाये, जनता पर दमन बंद किया जाये और तुरंत राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाये. भारत के माओवादियों के समर्थन में आयरिश जनता ने बैनर, झंडे उठा कर एकजुटता का प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने शहीदों को श्रधांजलि अर्पित करते हुए कामरेडाना एकजुटता का प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा संबंधों की इज्जत करते हैं और हर संघर्ष में साथ खड़े हैं.

उन्होंने इच्छा जताई कि उनके इस प्रदर्शन की खबर भारतीय कामरेडों तक भी पहुंचेगी. और पता चलेगा कि आयरलैंड की जनता भी उनका समर्थन करती है.

ब्राजील

ब्राजील कम्युनिस्ट पुनर्गठन यूनियन (सीआरयूबी) ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारत के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की. और भारत के तमाम क्रांतिकारियों, जनवादियों के प्रति समर्थन व बिनाशर्त एकजुटता की घोषणा की. उनका कहना था कि भारत की पूराना सामंती राज्य क्रांतिकारियों व जनवादियों को जेलों में ठूस रहा है. खासतौर से सीपीआई माओवादी के कार्यकर्ताओं को जो 1967 से भारतीय सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं.

मणीपुर

मणीपुर के रिक्शा चालकों व दुकानदारों ने काले झंडे लहरा कर व काले बैज लगाकर भारतीय सरकार का विरोध किया व राजनीतिक बंदियों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया.

यूएसए - एनसीपी (ओसी) द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति

हमारे संगठन का मानना है कि भारत के अंदर चल रहा युध्द दुनिया के पैमाने पर साम्राज्यवाद व क्राति के बीच जारी संघर्ष का मुख्य बिंदू है. और जो पार्टी इस युध्द का नेतृत्व एक अगवा दस्ते के रुप में कर रही है वह मार्क्सवाद के तीसरे चरण के रूप में माओवाद व सर्वहारा के वैश्विक सिध्दांत को लागू कर रही है.

यहां अमेरिका में, यहां भी बहुत सारे राजनीतिक बंदी हैं, जिनमें कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी और राष्ट्र मुक्ति योध्दा शामिल हैं, वह भी साम्राज्यवादी राज्य द्वारा आमानीवय यातनाओं का सामना कर रहे हैं.

हम साम्राज्यवादी केंद्र के कम्युनिस्टों के तौर पर भारतीय कामरेडों का पुरजोर समर्थन करते हैं जो भारतीय प्रतिक्रांतिकारी राज्य द्वारा अमानीय यातनाएं सह रहे हैं और उन हजारों शहीदों को श्रधांजलि अर्पित करते हैं जो वर्ग दुश्मन द्वारा लड़ाई या झूठी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं.

अमेरीकी साम्राज्यवादी राज्य भारतीय प्रतिक्रांतिकारी सरकार की पूरी पूरी मदद कर रहा है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी को कुचला जा सके. हम आपके बहादुराना त्याग व बलिदानों से प्रेरणा लेते हुए कार्य करते रहेंगे और लगातार भारतीय कामरेडों का रणनीतिक समर्थन करते रहेंगे.

स्पेन

Gran Marcha Hacia el counismo (साम्यवाद की ओर लांग मार्च) नामक ब्लॉग ने आइसीएसपीडब्बलू के आव्हान का खुलकर प्रचार किया और भारतीय राजनीतिक बंदियों की दुर्दशा व अमानीवय परिस्थितिया के खिलाफ जनता को जागरुक किया. ब्लॉग ने लिखा कि भारत को दुनिया के बड़े लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाता है लेकिन वहां पर राजनीतिक बंदियों से पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है.

पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा संपर्क आइसीएसपीडब्बलू के ब्लॉग पर दुनिया की राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, ट्रेड यूनियनों, क्रांतिकारी मीडिया व अन्य प्रगतिशील ताकतनों द्वारा किया गया. न केवल स्पेन बल्कि योरोपीयन, लेटिन अमेरीकन, एशिया व उत्तर अफ्रीका के देशों ने भी भारत के राजनीतिक बंदियों के समर्थन में आवाज उठाई. एक दर्जन से ज्यादा वेबसाइटों/ब्लॉगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जोरशोर के साथ प्रचार किया.

इटली

इटली में एक राष्ट्र व्यापी अभियान भारत के राजनीतिक बंदियों के समर्थन में छेड़ा गया. इसके तहत पर्चे, पोस्टरों, बैनरों से रोम, पालेरमो, मिलान, बेरगामो, टरांटो, बोलोगना, बेरेसीकीया, रेवेन्ना आदि शहरों में प्रचार किया गया.

रोम में छात्रों ने विश्वविद्यालय के बहार बैनर, पोस्टरों को लगा दिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कार्यलय के बहार एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया.

पालेरमो शहार में 7 जनवरी को अभियान के शुभारंभ की मीटिंग की गयी. 23 जनवरी को सामूहिक चंदा जमा कर रात्रिभोज का आयोजन कर सामूहिक रुप से माओवादी आंदोलन पर बनी फिल्म को देखा गया. 25 जनवरी को गलियों में प्रदर्शन का आयोजन किया गया.

टरांटो - 28 जनवरी को फिल्म चक्रव्यूह देखी गयी, उसके जरिये व्यापक जनता में प्रचार किया गया, देश की बड़ी फैक्टरियों व कारखानों में पोस्टर, बैनर लगाए गये.

ब्रेसीकिया - 19 जनवरी को दक्षिण एशीयाई व फिलिपंस के मजदूरों से एक आमसभा का अयोजन किया गया.

26 जनवरी को एक सभा का आयोजन कर चर्चा व अध्ययन किया गया.

जर्मनी

22 जनवरी को सामूहिक रुप से चक्रव्यूह फिल्म देखी गयी और 25 जनवरी को एक बजे से 2 बजे तक आमसभा का आयोजन किया गया.

फ्रांस, श्रीलंका में भी पर्चे और पोस्टर बांटे गए, वहीं श्रीलंका में सिंगली भाषा में भाकपा (माओवादी) के महासचिव कामरेड गणपति के हमंबर्ग सम्मेलन के संदेश को अनुवाद कर बांटा गया.

आस्ट्रीया

आस्ट्रीया - में भी एक आमसभा का आयोजन किया गया

आखिरी पेज से जारी...

नवीन पटनायक सरकार ने पंद्रह सालों में 172,000 करोड़ रुपये के समझौते (एमओयू) किये हैं. इन 49 कंपनियों में से 9 कंपनियां ही 70 प्रतिशत से ज्यादा पैसा लगाई हैं.

इसलिए आने वाला समय ओड़िशा को और बर्बादी की तरफ धकेलने वाला है क्योंकि गंदमर्धन, जगतसिंगपुर, कलाहंडी, रायगढ आने वाले समय में इन कंपनियों के बड़े निशाने हैं. लाखों आदिवासी जनता को विस्थापन करने की तैयारियां चल रही हैं. इस झूठे विकास के नाम पर फिर हजारों घरों व लाखों एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया जायेगा. क्या ऐसा आदमी या ऐसी पार्टी फिर से सत्ता में आने के काबिल है? क्या आप ऐसे नेता को फिर वोट देंगे जिसने अपने राज्य को विदेशी व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों को बेच दिया है? क्या आप उसे फिर सत्ता में लाओगे जिसने हजारों हेक्टेयर जंगल को कटवा दिया है?

राज्य में कांग्रेस, बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य पार्टियां भी नवीन पटनायक के सुर में सुर मिला कर काम करते हैं. यह राज्य में कहीं पर भी जनता के हित में आवाज नहीं उठाते. विपक्षी पार्टियां जनता के हित में कभी आवाज नहीं उठाती, जनता को भटका कर केवल अपनी सिटों को बढ़ाने के लिए कभी-कभी आजाव उठाने की नौटंकी करती है.

देश की मुक्ति के लिए, अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए माओवादी पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता, खासकर आदिवासी जनता संघर्ष कर रही है. इस संघर्ष की बदौलत उसने कई विदेशी व बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों की लूट को रोक दिया है. पोस्को, टाटा, बिरला, वेदांता, अंबानी, जिंदल आदि के साथ केंद्र व रज्य सरकार ने कई एमओयू साइन कर रखे हैं. माओवादी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गयी है, क्योंकि उनकी लूट नहीं चलने देती. इसलिए शोषक-शासक वर्गो ने आपरेशन ग्रीनहंट की शुरुआत की और आज सारी पार्टियां बिजू जनता दल, बिजेपी हो या कांग्रेस, माकपा हो या भाकपा सभी ग्रीनहंट के नाम पर देश की अपनी ही जनता पर युध्द छेड़ने के लिए एकजुट हैं. कोई भी पार्टी जो चुनावों में खड़ी है इस अन्यायपूर्ण युध्द का विरोध नहीं करती. अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए अपने ही देश की सेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों को उतारा जा रहा है, सैकड़ों गांव तबाह करा दिये जा चुके हैं, दर्जनों महिलाओं से बलात्कार किये जा चुके हैं, नियमगिरी, लांजीगढ़, गंदमर्धन, सोनाबेड़ा, मैनपुर, उदंती सब जगह दमन का तांडव जारी है.

ओड़िशा के कोरापुट, मलकानगिरी, बरगढ़, बलांगिर, नारायणपटना, नियमगिरी में कृषि क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए,नवजनवादी क्रांति की सफलता माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जारी सशस्त्र आंदोलनों, जन आंदोलनों को फासीवादी तरीके से कुचला जा रहा है. हजारों की संख्या में जनता को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया है और दर्जनों नौजवानों को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया.

छत्तीसगढ़ के सितानदी, उदंती, आमामोरा से लेकर सोनाबेड़ा तक टाईगर रिजर्व के नाम पर जनता को उजाड़ने की साजिश से काम जोरों पर चल रहा है. जहां टाईगर ही नहीं है वहां से आदिवासी जनता को उजाड़ा जा रहा है. उनको वनोपजों का संग्रहण तक नहीं करने दिया जा रहा.

अगर हमें सही जनवाद, मुक्ति और विकास चाहिए तो वह दंडकारण्य, बिहार-झारखंड के रास्ते से ही हो सकता है. आइये चुनावों का बहिष्कार करते हुए, झूठे वायदों को लात मारते हुए भूखमरी, पलायन, विस्थापन के खिलाफ संघर्ष को तेज करें.

ओड़िशा के मजदूर-किसानों, छात्र-बुध्दिजीवियों, दुकानदार-कर्मचारियों, महिलाओं सहित सारी जनता से हमारी पार्टी आव्हान करती है कि इन झूठे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करे और राज्य को साम्राज्यवाद, समांतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के पंजों से छुड़वाने के लिए माओवाद की राह चुने. पीएलजीए में भर्ती होकर नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करे!

चुनाव एक तमाशा है - संघर्ष ही एक आशा है!

नोट से न वोट से - हक मिलेंगे चोट से!

नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संगठित होकर संघर्ष तेज करो!

जो जनता को उजाड़े वह सरकार निकम्मी है! चुनावों का बहिष्कार करो!

ओड़िशा विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

विदेशी कंपनियों व बड़े पूंजपतियों की दलाल
नवीन पटनायक सरकार को मार भागाओ!
ओड़िशा को बेचकर खाने वाली तमाम बुर्जुआ पार्टियां मुर्दाबाद!
ओड़िशा को बचाने के लिए विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो माओवाद की राह चुनो!

प्यारी ओड़िशा जनता

लोकसभा चुनावों के साथ-साथ ओड़िशा विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. नवीन पटनायक सरकार पूरे गाजे-बाजे के साथ चुनाव में उतर गयी है और ओड़िशा के विकास के नाम पर वोट मांग रही है. लेकिन सवाल उठता है कि पिछले पंद्रह सालों में नवीन 'बाबू' की सरकार में किसका विकास हुआ है? आज भी ओड़िशा गरीबी और भुखमरी, विस्थापन व पलायन के लिए पूरे देश में बदनाम हैं, लोगों ने आम की गुठलियां खाकर इसी राज्य में जान दी हैं क्योंकि अनाज नहीं मिलता! ओड़िशा में टाटा, रिलायंस, जिंदल, पोस्को, मित्तल, वेदांता, हिंडालको, स्टारलाईट, वेलस्पुन पावर एंड स्टील, नालको का विकास हुआ है. उन्होंने हजारों करोड़ रुपये यहां से कमाई कर अपनी कंपनियों की संख्या दुगनी कर ली है लेकिन ओड़िशा जनता को पहले से ही आधे पेट रहने पर मजबूर है और पिछले पंद्रह सालों में यह आधे से भी आधा रह गया है. नवीन पटनायक विदेशों में दौरे कर पूंजीपतियों को न्यौता देकर बुलाता है कि ओड़िशा में 5231 करोड़ टन लोह के भंडार हैं, जो देश के कुल भंडारों का 35 प्रतिशत है आइये ये आपके लिए ही है. राज्य में 27 किस्म की खदाने हैं जो अरबों करोड़ों रुपयों का उत्पादन करती है. लेकिन जनता के हिस्से उस में से कुछ भी नहीं आता. तो यह विकास किसका केवल बड़े पूंजीपतियों का ही विकास है बाकि जनता का केवल विनाश और विनाश है!

2013 में आये तुफान के बाद लाखों किसानों की फसल तबाह हो गयी. सरकार ने प्रचार किया कि उस पर हमने जीत हासिल कर ली, जनता का नुकसान नहीं होने दिया, मगर कई लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया.

इसका कारण है केवल और केवल बड़े पूंजीपति, विदेशी कंपनियां व दलाल राजनीतिक पार्टियां. पिछले पन्द्रह सालों से बिजू जनता दल की नवीन पटनायक सरकार सत्ता में है, जबकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, विधानसभा में और भी कई पार्टियां हैं - लेकिन ये सभी पार्टियां जनता को लूटने के लिए, विदेशी कंपनियों, टाटा, जिंदल, बिरला, वेदांता, पोस्को, अंबानी जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एकजुट हैं, विरोध का मात्र दिखावा कर रही है.

नियमगिरी, लांजीगढ़, नारायणपटना, काशिपुर, जगतसिंगपुर, कलिंगनगर, गंदमर्धन, लोयर सुकतेल इलाके की जनता अपनी खनिज संपदा, जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन राज्य की बिजू जनता दल और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एकजुट होकर जनता पर युध्द छेड़ दिया. दर्जनों जनता को गोलियों से भून दिया, पोस्को का विरोध कर रहे महिलाओं, बच्चों पर अकथनीय जुल्म ढाए गए. जनता विरोध के बावजूद आज पोस्को को मंजूरी दे दी गयी है. वेदांता को और दूसरी जगह पांच 'मालियों'(पहाड़ों) पर खनन करने की अनुमति दे दी है.

पंचकुड़ी के जंगलों में तीन लोगों की झूठी मुठभेड़ में हत्या कर उनको माओवादी घोषित किया गया ताकि जनता में दहशत फैला कर सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर चल रही 'पाली सभाओं' को विफल किया जा सके. कलिंगनगर में 12 लोगों को फायरिंग कर मार डाला. क्योंकि वह टाटा के खिलाफ लड़ रहे थे. गंदमर्धन में माधव सिंग ठाकूर और रमेश साहू को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया.

राज्य में अल्पसंख्यकों, दलितों व आदिवासियों पर भगवा आतंकवादियों के हमले जारी हैं, नवीन पटनायक सरकार उनका भरपुर समर्थन कर रही है. कंधमाल में जनता के दुश्मन लक्ष्मणनंद सरस्वती के सफाये के बाद कितने ही निर्दोष इसाइयों, आदिवासियों को मार डाला गया, उनके घरों व गिरजाघरों को जला दिया गया. महिलाओं पर अत्याचार किये गए. स्थानीय पुलिस व एसओजी बलों ने दंगाइयों का ही साथ दिया. उन्होंने ने भी महिलाओं पर अत्याचार किये. उल्टा आज कोर्ट ने कई दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को आजीवन कारावास तक की सजा सुना दी है.

बलांगिर जिला के लाटूर में दलित बस्ती पर हमला किया गया, दलितों के साथ साथ मारपीट की गयी, उनके घरों पर तेल छिड़क कर पूरी बस्ती को जलाकर रख कर दिया. उनको बस्ती से भगा दिया गया. यह हमला दारु माफिया, कई दारु भट्टियों के मालिक घासीराम अग्रवाल ने करवाया. नवीन पटनायक सरकार इसे पूरी सह देती है.

इतना ही नहीं शाह आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ओड़िशा में खनन कंपनियां हजारों करोड़ों का अवैध खनन कर रही है. नवीन पटनायक शासनकाल में लगभग 54000 करोड़ का खनन घोटाला सामने आया, कोल ब्लॉक आवंटन दाल घोटाला सामने आया. यह तो सामने आया है इसके अलावा पता नहीं कितने और घपले हुए हैं.

बचा हुआ पिछले पेज पर....